FORTUNE TMT
PANORA 2026
THE PROPERTY FEST

RNI NO PUNBIL/2014/59416
UTURNTIME.COM

यूटर्न टाइम

The Good, Bad and Ugly of India
FOLLOW US ON @UTURNTIMENEWS

Date
10-11th April, 2026
Time
10 am to 8:00 pm
Venue
Nirvana Luxury Hotel, Ludhiana

VOL: 11 | ISSUE 79 | THURSDAY 02-04-2026 | RS-03 | PAGE-12 | PUBLISHED BY: LUDHIANA | HINDI DAILY NEWSPAPER Visit at : www.uturntime.com

HS फूलका रिटर्न्स: AAP का पूर्व चेहरा पंजाब की अहम सियासी चाल में BJP में शामिल

चंडीगढ़/यूटर्न/1 अप्रैल। वरिष्ठ वकील और जाने-माने मानवाधिकार वकील हरविंदर सिंह फूलका, जिन्हें 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए लगातार किए गए प्रयासों के लिए व्यापक रूप से पहचाना जाता है, 1 अप्रैल, 2026 को भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल होकर सक्रिय राजनीति में फिर से लौट आए हैं।

उनके इस कदम को 2027 के पंजाब विधानसभा चुनावों से पहले एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम के रूप में देखा जा रहा है, और इसे 2027 के पंजाब विधानसभा चुनावों से पहले BJP के लिए एक बड़ी जीत माना जा रहा है। फूलका नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इखढ में शामिल हुए। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, पंजाब BJP अध्यक्ष सुनील जाखड़, दिल्ली BJP प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा और राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ जैसे नेता मौजूद थे। राजनीति में उनकी वापसी सात साल के अंतराल के बाद हुई है; इस दौरान वे अपने कानूनी और वकालत के काम को जारी रखते हुए चुनावी भूमिकाओं से काफी हद तक दूर रहे थे।

कौन हैं HS फूलका ?

हरविंदर सिंह फूलका, जिन्हें आमतौर पर 'फूलका' के नाम से जाना जाता है और जिन्होंने पहले दाखा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था, ने 2014 में आम आदमी पार्टी (AAP) के साथ अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की थी। उसी वर्ष उन्होंने लुधियाना से लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन कांग्रेस नेता रवनीत सिंह बिट्टू से हार गए। हालाँकि, 2017 के पंजाब विधानसभा चुनावों में उन्होंने अकाली दल के नेता मनप्रीत सिंह अयाली को हराकर निर्णायक जीत हासिल की, और बाद में पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में कार्य किया। 2018 में, फूलका ने अपने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने इसके पीछे 2015 के बेअदबी मामलों से निपटने के तरीके को लेकर कांग्रेस सरकार के प्रति अपनी असंतोष व्यक्त किया था। इस कदम ने एक सिद्धांतवादी और मुद्दों पर आधारित राजनीति करने वाले नेता के रूप में उनकी छवि को और मजबूत किया। दिसंबर 2024 में, वे कुछ समय के लिए शिरोमणि अकाली दल (रअऊ) के साथ जुड़े थे; यह जुड़ाव पार्टी के भीतर धार्मिक नेतृत्व के तहत किए जा रहे पुनर्गठन के प्रयासों के बाद हुआ था। राजनीति से परे, फूलका की विरासत उनके कानूनी सक्रियतावाद में गहराई से निहित है। दशकों से, वे 1984 की हिंसा के दोषियों को जवाबदेह ठहराने के प्रयासों में सबसे आगे रहे हैं, और स्वतंत्र भारत की कुछ सबसे लंबी और जटिल कानूनी लड़ाइयों में पीड़ितों का प्रतिनिधित्व किया है। BJP में उनका शामिल होना न केवल एक राजनीतिक बदलाव का संकेत है, बल्कि यह इस बारे में भी सवाल खड़े करता है कि पंजाब की राजनीति के बदलते परिदृश्य में, मानवाधिकारों के लिए उनकी लंबे समय से चली आ रही वकालत उनकी नई राजनीतिक भूमिका के साथ कैसे तालमेल बिठाएगी।

सिविल सर्जन कार्यालय में पुरुष कर्मचारियों के लिए सुलभ शौचालय नहीं

लुधियाना यूटर्न 1 अप्रैल सहगल सिविल सर्जन कार्यालय में पुरुष कर्मचारियों के लिए सुलभ शौचालय न होने के कारण कर्मचारियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है जबकि ऐसी ही शिकायत कई महिला कर्मचारियों की भी है उल्लेखनीय है कि जो शौचालय सिविल सर्जन कार्यालय में बना हुआ था वह कई हफ्तों से बंद पड़ा हुआ है जिससे कर्मचारी भारी परेशानी में दिखाई दे रहे हैं ऐसे में सुपरिंटेंडेंट कार्यालय में बना शौचालय जैन शौचालय बना हुआ है इसके अलावा कार्यालय के पिछली तरफ पड़े कूड़े के के देर भी सिविल सर्जन कार्यालय की शोभा में ग्रहण लगा रहा हैं।

श्री राम राम शरणं, भव राम राम ॥

With profound grief and a heavy heart, we inform you of the sad and untimely demise of our dear

Sh. Narinder Nath Mahajan

We humbly request your presence to join us in offering prayers for the peace of the departed soul.
Date: 2nd April, 2026
Time: 2:00- 3:00 pm (Lunch: 1:00 pm onwards)
Venue: Navdurga Mandir, Sarabha Nagar, Ludhiana
Contact: 8070500008, 9803072720

Lovingly Remembered By

Ravi Mahajan — *Tony Mahajan*
Nalin Mahajan — *Dipin Mahajan*
Ravi Industries — *Mahajan Engg. Works*
Hippo Bikes Pvt. Ltd. — *Hippo Special Steels Pvt. Ltd.*
Flying Stag Bikes Pvt. Ltd — *Mahajan Engg. Works India Pvt. Ltd.*

यूटी सचिवालय घेराव की तैयारी पूरी, 2 अप्रैल को सड़कों पर उतरेंगे कर्मचारी

चंडीगढ़/यूटर्न/01 अप्रैल। यूटी चंडीगढ़ में सरकारी व नगर निगम कर्मचारियों द्वारा 2 अप्रैल को यूटी सचिवालय के घेराव की तैयारी तेज हो गई है। कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ गवर्नमेंट एंड एमसी इंप्लाइज एंड वर्कर्स के आह्वान पर विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने शहर के अलग-अलग सेक्टरों में बैठकें कर आंदोलन को सफल बनाने की रणनीति बनाई। पब्लिक हेल्थ, वाटर सप्लाई, बिजली, सिविल, सीवर, हॉर्टिकल्चर और रोड वर्कर्स यूनियन सहित कई यूनियनों ने सेक्टर 4, 17, 23, 26, 29, 33, 34, 35, 42, 43, 46 और मनीमाजरा समेत अन्य स्थानों पर मीटिंग्स कीं। मीटिंगों में नेताओं ने आरोप लगाया कि चंडीगढ़ प्रशासन कर्मचारियों की मांगों के प्रति गंभीर नहीं है और बातचीत से भी बच रहा है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी पिछले कई महीनों से रैलियां, प्रदर्शन और भूख हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा। कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में समान काम के लिए समान वेतन, कॉन्ट्रैक्ट वर्करों को नियमित करना, समय पर वेतन भुगतान, खाली पदों को भरना और रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन लाभ देना शामिल है।

Celebrate your Birthday or Anniversary with UTURN TIME in association with

Hot Breads

0161-4603333, 5012222

2 LUCKY WINNERS WILL GET CAKE WORTH OF ₹1200 EACH

*WINNERS WILL BE DECIDED THROUGH LUCKY DRAW *T&C

FOR MORE DETAILS, CALL: 99882-20063, 98142-95372
janhetaishi@gmail.com, hetaishinews@gmail.com

All rights about Distribution & Offer will be reserved by U-TURN TIME MANAGEMENT Only.

गुस्ताखी माफ

अगर मुकदमे चल रहे, चलने दें सरकार।
जजों-वकीलों के चलें, इससे घर-परिवार।
इससे घर-परिवार, अगर निपटेंगे जल्दी।
कहिए कैसे चले, घरों का आटा-हल्दी।
कह साहिल कविराय, सुखा दें कैसे चश्मे।
चलने दें सरकार, चल रहे अगर मुकदमे।

- डॉ. राजेन्द्र साहिल

जोगिंद्रा ग्रुप का ₹1,100 करोड़ निवेश, पंजाब के उद्योग और ग्रीन ऊर्जा को मिलेगा बड़ा बढ़ावा

चंडीगढ़/यूटर्न/01 अप्रैल। पंजाब में औद्योगिक विकास को नई रफ्तार मिलने जा रही है। राज्य के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री Sanjeev Arora ने जानकारी दी कि Jogindra Group द्वारा 1,100 करोड़ रुपये के बड़े निवेश की घोषणा की गई है, जिससे प्रदेश में उद्योग और ग्रीन ऊर्जा सेक्टर को मजबूती मिलेगी।

मंत्री ने बताया कि इस निवेश में 700 करोड़ रुपये स्टील क्षेत्र में लगाए जाएंगे, जो मुख्य रूप से जोगिंद्रा कास्टिंग्स और वर्धमान आदर्श के माध्यम से होंगे। वहीं 400 करोड़ रुपये का निवेश जोगिंद्रा ग्रीन इंडिया के जरिए नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में किया जाएगा। यह कदम पंजाब में निवेशकों के बढ़ते विश्वास और उद्योग-अनुकूल नीतियों का प्रमाण है।

Sanjeev Arora के अनुसार, इस विस्तार से जोगिंद्रा ग्रुप का टर्नओवर 3,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 5,000 करोड़ रुपये तक पहुंचने की संभावना है। साथ ही कर्मचारियों की संख्या 1,800 से बढ़कर 3,000 हो जाएगी, जिससे बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता भी 37 मेगावाट से बढ़कर 120 मेगावाट तक पहुंचने की उम्मीद है। 1992 में स्थापित जोगिंद्रा ग्रुप उत्तरी भारत का एक प्रमुख औद्योगिक समूह है, जो स्टील निर्माण के क्षेत्र में अपनी मजबूत पहचान रखता है और अब ग्रीन एनर्जी में भी तेजी से विस्तार कर रहा है। समूह का नेतृत्व सीएमडी आदर्श गर्ग, डायरेक्टर संजय गुप्ता और निमित गुप्ता कर रहे हैं।

मंत्री ने कहा कि मंडी गोबिंदगढ़, जो पहले से ही पंजाब के स्टील उद्योग का प्रमुख केंद्र है, इस निवेश से और सशक्त होगा। उन्होंने Bhagwant Singh Mann सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि राज्य में उद्योग-अनुकूल माहौल और आसान कारोबार प्रणाली को बढ़ावा देकर ऐसे निवेशों को लगातार प्रोत्साहित किया जाएगा।

आवारा कुत्तों पर नियंत्रण का प्रोजेक्ट विवादों में, नगर परिषद और संस्था आमने-सामने

जीरकपुर/यूटर्न/01 अप्रैल। शहर में आवारा कुत्तों की बढ़ती समस्या को नियंत्रित करने के लिए शुरू किया गया एनिमल बर्थ कंट्रोल (एबीसी) प्रोग्राम प्रशासनिक असमंजस और आपसी तालमेल की कमी के चलते विवादों में घिर गया है। नगर परिषद जीरकपुर और कावा संस्था के बीच पत्राचार से यह स्पष्ट हुआ है कि प्रोजेक्ट को शुरू करने को लेकर दोनों पक्षों में गंभीर मतभेद उत्पन्न हो गए हैं। जानकारी के अनुसार, नगर परिषद ने कावा को डॉग स्टरलाइजेशन प्रोजेक्ट का कार्यादेश जारी किया था, जिसके बाद संस्था ने नियमों के तहत एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया से मान्यता के लिए आवेदन किया। एनिमल बर्थ कंट्रोल नियम 2023 के अनुसार, ऐसे किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले बोर्ड की मंजूरी लेना अनिवार्य होता है। कावा का कहना है कि नगर परिषद द्वारा उन्हें स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि बोर्ड की मंजूरी मिलने के बाद ही कार्य शुरू किया जाए। इसी कारण सभी तैयारियां पूरी होने के बावजूद प्रोजेक्ट को शुरू नहीं किया गया। हालांकि बाद में नगर परिषद ने एक मेमो जारी कर संस्था पर कार्य शुरू न करने का आरोप लगाते हुए तीन दिनों के भीतर काम शुरू करने का नोटिस दे दिया, जिससे विवाद और गहरा गया।संस्था ने इस पर कड़ा एतराज जताते हुए कहा है कि उन्होंने हर कदम नगर परिषद के निदेर्शों के अनुसार उठाया है और देरी उनकी ओर से नहीं, बल्कि बोर्ड की निरीक्षण और स्वीकृति प्रक्रिया के कारण हुई है, जो उनके नियंत्रण से बाहर है। कावा ने नगर परिषद के समक्ष यह भी प्रश्न उठाया है कि क्या बिना अंतिम मंजूरी के प्रोजेक्ट शुरू किया जाए या नियमों के अनुसार स्वीकृति मिलने के बाद ही कार्य प्रारंभ किया जाए। साथ ही संस्था ने मांग की है कि मंजूरी मिलने तक की अवधि को अनुबंध की समय-सीमा में शामिल न किया जाए। विशेषज्ञों का मानना है कि एबीसी प्रोग्राम शहर में आवारा कुत्तों की संख्या नियंत्रित करने और मानव-जानवर संघर्ष को कम करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। ऐसे में प्रशासनिक अस्पष्टता के कारण इस प्रोजेक्ट का अटकना सीधे तौर पर आम लोगों को प्रभावित कर सकता है।

पहले भी सफल रहा है प्रोजेक्ट

कावा ने बताया कि वर्ष 2024 से जुलाई 2025 तक वह जीरकपुर में एबीसी प्रोग्राम का सफल संचालन कर चुकी है। इस बार देरी केवल प्रक्रियात्मक कारणों से हो रही है।

'हमारी ओर से किसी प्रकार की देरी नहीं है। हम किसी भी गैरकानूनी कार्य को प्राथमिकता नहीं देंगे और कानून के दायरे में रहकर ही काम करेंगे। कावा को आवश्यक एनओसी या दस्तावेजों के लिए कहीं नहीं रोका गया है। यदि संस्था एक सप्ताह के भीतर कार्य शुरू नहीं करती, तो टेंडर रद्द कर दिया जाएगा।'

— परविंदर सिंह भट्टी, कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद जीरकपुर

निकाले गए कर्मचारियों के समर्थन में संयुक्त किसान मोर्चा व ट्रेड यूनियनों का संघर्ष तेज करने का ऐलान

डेराबस्सी/यूटर्न/01 अप्रैल। गांव दप्पर स्थित भारतीय किसान यूनियन (लखोवाल) के कार्यालय में संयुक्त किसान मोर्चा और विभिन्न ट्रेड यूनियनों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में सुखमणि इंटरनेशनल स्कूल, डेराबस्सी द्वारा कथित रूप से गैरकानूनी तरीके से नौकरी से निकाले गए कर्मचारियों के मुद्दे पर गंभीर चर्चा की गई। बैठक में सभी संगठनों ने स्कूल प्रबंधन द्वारा कर्मचारियों के साथ किए जा रहे व्यवहार की कड़ी निंदा की और निर्णय लिया कि निकाले गए कर्मचारियों को दोबारा नौकरी पर बहाल करवाने के लिए संघर्ष को और तेज किया जाएगा। इस संबंध में 3 अप्रैल 2026 को सुबह 11 बजे सुखमणि इंटरनेशनल स्कूल के बाहर चल रहे धरना स्थल पर एक संयुक्त विशाल बैठक बुलाने का फैसला लिया गया है, जिसमें आगामी रणनीति की घोषणा की जाएगी। एटक पंजाब के उपाध्यक्ष विनोद चुघ ने सभी इंसाफ पसंद संगठनों, संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं, ट्रेड यूनियनों और मजदूर वर्ग से अपील की कि वे 3 अप्रैल को बड़ी संख्या में धरने में पहुंचकर कर्मचारियों के साथ हो रही कथित नाइंसाफी के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाएं। बैठक में भारतीय किसान यूनियन (लखोवाल) के नेता मनप्रीत सिंह और रणजीत सिंह, कुल हिंद किसान सभा के नेता सुरिंदर सिंह जड़ोत और बलविंदर सिंह जड़ोत, एटक के उपाध्यक्ष विनोद चुघ, हर्नाम सिंह बाकरपुर तथा शिक्षा संस्थान वर्कर यूनियन (एटक) के नेता कमलजीत सिंह और बलजीत सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहे।

यूटर्न टाइम
The Good, Bad and Ugly of India

पेज 06 श्री शारदा माता मंदिर में चतुर्दशी भंडारे का...

आखिरकार 3 साल 9 दिन 16 घंटे पहले मंत्री अरोड़ा द्वारा शहरवासियों को दिखाया सपना हुआ पूरा, हलवारा एयरपोर्ट से 15 मई को विमान लेंगे उड़ान

एयरपोर्ट की क्रेडिट वार ने बजाया विस चुनाव 2027 का बिगुल

राजदीप सिंह सैनी

लुधियाना/यूटर्न/1 अप्रैल। 3 साल 9 दिन 16 घंटे बाद मंत्री संजीव अरोड़ा द्वारा लुधियाना शहरवासियों को दिखाया सपना पूरा होने जा रहा है। दरअसल, 15 मई को एयरपोर्ट से पहली फ्लाइट उड़ने जा रही है। यह फ्लाइट दिल्ली और लुधियाना के बीच उड़ेगी। यह 160 सीटों वाला एयरबस E320 जहाज होगा। जिसकी टिकट कीमत 4436 रुपए होगी। जिसकी एक अप्रैल से टिकट बुकिंग शुरू हो चुकी है। इसका ऐलान पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा द्वारा किया गया। जिनकी और से इसकी शुरूआत के लिए कड़े प्रयास किए गए थे। हालांकि फ्लाइट बुकिंग और पहली फ्लाइट शुरू होने की तारीख को लेकर मंत्री संजीव अरोड़ा और केंद्रीय राज्यमंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बीच जमकर सोशल मीडिया जंग चली। दरअसल, बुधवार को मंत्री संजीव अरोड़ा द्वारा दोपहर करीब 2 बजे टिकट बुकिंग की घोषणा को लेकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट डालकर जानकारी सांझी की गई। वहीं कुछ देर बाद राज्यमंत्री रवनीत बिट्टू ने भी पोस्ट डाल दी। अभी बिट्टू द्वारा अपडेट दिया जा रहा था कि इस बीच मंत्री अरोड़ा द्वारा अपनी पहली टिकट भी बुक करवा दी गई। जबकि दूसरी टिकट उनकी पत्नी संध्या अरोड़ा द्वारा बुक की गई है।

सोशल मीडिया पोस्टों ने बढ़ाई सियासी गर्मी

मंत्री संजीव अरोड़ा द्वारा जैसे ही बुधवार दोपहर कुछ समय में हलवारा एयरपोर्ट से फ्लाइट टिकट बुकिंग शुरूआत की पोस्ट डाली गई, सोशल मिडिया पर सियासी गर्मी बढ़ गई। जिसके कुछ ही समय बाद चलते एमओएस रवनीत बिट्टू ने भी सोशल मिडिया पर पोस्ट कर १५ मई से फ्लाइट शुरू होने और फ्लाइट के टाइमिंग की जानकारी साँझा कर डाली ! राजनितिक गलियारे ने इसे क्रेडिट वार का नाम दिया।

एयरपोर्ट क्रेडिट पंजाब विधानसभा चुनाव २०२७ का बिगुल

एक्सपर्ट्स की माने तो विभिन्न राजनेताओं और पार्टियों द्वारा हलवारा एयरपोर्ट और फ्लाइट्स शुरू होने के क्रेडिट लेने की होड़ को पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 का बिगुल की संज्ञा दी। हलवारा एयरपोर्ट की शुरूआत ने कहीं न कहीं सियासत में हलचल पैदा कर दी है।

यह रहेगा फ्लाइट का समय...

बता दें कि हलवारा एयरपोर्ट से अभी दिल्ली और लुधियाना के बीच दो फ्लाइटों की शुरूआत की गई है। जिसकी टिकट कीमत कुल 4436 रुपए होगी। अभी फ्लाइट में सिर्फ इकोनॉमी क्लास के लिए बुकिंग शुरू की गई है। यह फ्लाइट 15 मई को सुबह 5 :55 बजे दिल्ली से चलेगी, जो कि लुधियाना 7 :05 बजे पहुंचेगी। इसमें कुल समय 1 घंटा 10 मिनट लगेगें। दूसरी फ्लाइट दिल्ली से 12 :55 बजे लुधियाना के लिए उड़ेगी। वहीं लुधियाना से पहली फ्लाइट सुबह 7 :55 बजे उड़ेगी, जो दिल्ली 9 :10 बजे पहुंचेगी। दूसरी फ्लाइट दोपहर 2 :40 बजे हलवारा से उड़कर 3 :55 बजे दिल्ली पहुंचेगी।

फ्लाइट के लिए स्पेशल दिल्ली पहुंचेगें लोग

वहीं इस फ्लाइट में सफर के लिए लुधियाना वासी बेहद उत्सुक है। लोग इस फ्लाइट के पहले सफर का आनंद लेना चाहते हैं। जिसके चलते लोगों द्वारा 15 मई की सुबह दिल्ली से लुधियाना फ्लाइट की बुकिंग करवाई गई है। इसके लिए वह 14 मई की रात ही दिल्ली पहुंच जाएंगे, ताकि वह 15 मई को फ्लाइट का आनंद लेते हुए वापिस लुधियाना आ सके। बताया जा रहा है कि टिकट ओपन होते ही मिनटों में सभी बुक हो गई। वहीं कहा जा रहा है कि 50 प्रतिशत टिकटें लुधियाना वासियों ने बुक की।

अरोड़ा दंपति ने करवाई पहली टिकट बुक

वहीं टिकट बुकिंग ओपन होते ही मंत्री संजीव अरोड़ा द्वारा पहली टिकट अपनी बुक की गई। वहीं दूसरी टिकट उनकी पत्नी संध्या अरोड़ा द्वारा बुक करवाई गई है। बता दें कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हलवारा एयरपोर्ट का उद्घाटन किया तब सेहत के खराब होने के कारण मंत्री अरोड़ा इस समागम में शामिल नहीं हो सके थे। मगर अब दरुस्त होने के बाद इस जहाज का सफर करने के लिए वह सबसे आगे हैं।

मुझे गर्व कि मैं शहर के लिए कुछ कर सका

- वहीं इस एयरपोर्ट के निर्माण की शुरूआत से लेकर फ्लाइट चलने तक मंत्री संजीव अरोड़ा द्वारा अनथक प्रयास किए गए थे। जिसके चलते टिकट बुकिंग और फ्लाइट तारीख की घोषणा के बाद उन्होंने कहा कि मुझे गर्व है कि मैं अपने शहर के लिए कुछ कर सका। उन्होंने कहा कि जनता द्वारा उन्हें वोट डालकर चुना गया, तो आज उनका भी फर्ज बनता था कि वह जनता को उनकी वोट का मूल्य दें।

क्रेडिट लेने आगे आ रहे पार्टियां और लीडर

- बुद्धिजीवियों का मानना है की क्रेडिट वार कोई नहीं बात नहीं है जब भी कोई बड़ा काम शुरू होता है तो काम कराने बेशक कोई आगे न आए। लेकिन जब काम पूरा हो जाता है, तो सभी आगे आकर क्रेडिट लेने का प्रयास करते हैं। हलवारा एयरपोर्ट को लेकर भी यही देखने को मिला है।

हर सरकार ने बनाया मुद्दा

- वर्ष 2004 से हर पार्टी ने एयरपोर्ट को मुख्य चुनावी मुद्दा बनाकर वोट मांगे और समय समय लुधियानवियों को ठगा है। लेकिन मंत्री अरोड़ा द्वारा राज्यसभा मेंबर बनने के बाद इस सपने को दोबारा सजोया। जिसके बाद 3 साल 9 दिन 16 घंटे की मेहनत के बाद यह सपना पूरा हो सका।

कुछ यूं रहा मंत्री अरोड़ा व आप पार्टी का एयरपोर्ट निर्माण को लेकर सफर

- 22 नवंबर 2022 को पंजाब के सीएम भगवंत मान के हस्तक्षेप से इस रुकी हुई परियोजना को दोबारा गति मिली।
- 11 दिसंबर 2022 को 50 करोड़ रुपये की राशि जारी कर निर्माण कार्य फिर से शुरू कराया गया।
- 17 जनवरी 2023 को सांसद रहते हुए संजीव अरोड़ा ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय से दिल्ली–लुधियाना उड़ानें बहाल करने की मांग उठाई।
- 14 अप्रैल 2023 को उन्होंने सभी एयरलाइंस को पत्र लिखकर हलवारा से उड़ानें शुरू करने की अपील की।
- 7 मई 2023 को एयरपोर्ट के निर्माण कार्य को तेजी से पूरा करने की मांग रखी।
- 22 अगस्त 2023 को नागरिक उड्डयन सचिव राजीव बांसल से मंजूरी मिलने के बाद एयरलाइंस पर दिल्ली और मुंबई उड़ानें शुरू करने का दबाव बनाया गया।
- 26 अगस्त 2023 को सांसद अरोड़ा ने एयरपोर्ट का दौरा कर प्रगति का जायजा लिया।
- 2024 में भी प्रयास जारी रहे।
- 9 जनवरी को मंत्रालय ने निर्माण प्रगति की जानकारी दी, जबकि 31 जनवरी को अंतरिम टर्मिनल भवन के उद्घाटन की मांग की गई।
- 19 जुलाई 2024 को संजीव अरोड़ा ने एएआई, पीडब्ल्यूडी और भारतीय वायु सेना के अधिकारियों के साथ निर्माण कार्य की समीक्षा की।
- 13 अगस्त 2024 को उन्होंने नटराजन चंद्रशेखरन से मुलाकात कर उड़ानों पर चर्चा की।
- 29 अगस्त को एयर इंडिया के अधिकारियों से गुरुग्राम में बैठक कर जल्द उड़ानें शुरू करने का आश्वासन लिया।
- 3 सितंबर 2024 को उन्होंने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री को पत्र लिखकर प्रक्रिया तेज करने की मांग दोहराई।
- 21 दिसंबर 2024 को एएआई चेयरमैन विपिन कुमार के साथ बैठक में एयरपोर्ट कोड और संचालन तिथि पर चर्चा हुई।
- जनवरी 2025 में एयर इंडिया ने स्पष्ट किया कि सभी मंजूरियों के बाद उड़ानें शुरू की जाएंगी और 10 जनवरी को हलवारा से संचालन के लिए सहमति दे दी।
- 4 फरवरी 2025 को एयरपोर्ट को एचडब्ल्यूआर कोड मिला, जबकि 19 फरवरी को अंतिम चरण के कार्यों की समीक्षा की गई।
- 23 मई 2025 को मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र से सहनेवाल की उड़ानों को हलवारा शिफ्ट करने की मांग की।
- जून 2025 तक निर्माण कार्य पूरा हो गया और टर्मिनल भवन की फिनिशिंग भी समाप्त हो गई।
- 27 जुलाई 2025 को प्रस्तावित उद्घाटन तकनीकी कारणों से टाल दिया गया। इसके बाद 2 दिसंबर 2025 को राज्यसभा में राजिंदर गुप्ता ने एयरपोर्ट को जल्द शुरू करने की मांग उठाई।
- 29 दिसंबर 2025 को एयर इंडिया ने सप्ताह में पांच दिन उड़ान संचालन की मंजूरी दी।
- 2026 में अंतिम तैयारियां पूरी हुईं। 15 जनवरी को सुरक्षा ऑडिट पूरा हुआ और बीसीएएस से मंजूरी मिली।
- 28 जनवरी को अंतिम निरीक्षण किया गया और 29 जनवरी को पीएमओ से उद्घाटन की पुष्टि मिली।
- अंततः 1 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली हलवारा एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन किया।

2026 के आखिर में पंजाब विधानसभा चुनाव? जोरदार चर्चा, लेकिन इसकी कितनी संभावना है?

चंडीगढ़/यूटर्न/1 अप्रैल। एक ऐसा कदम जो पंजाब की राजनीतिक समय-सीमा को काफी हद तक बदल सकता है—ऐसे मजबूत संकेत मिले हैं कि राज्य विधानसभा चुनाव अपने तय समय (2027 की शुरूआत) से कई महीने पहले, 2026 के आखिर या जनवरी 2027 की शुरूआत में करवाए जा सकते हैं। हालाँकि, अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक हलकों के कई सूत्रों का कहना है कि इस विचार पर अब गंभीर आंतरिक विचार-विमर्श चल रहा है। अगर यह कदम उठाया जाता है, तो यह राज्य की चुनावी योजना में एक बड़ा रणनीतिक बदलाव होगा। इससे सत्ताधारी आम आदमी पार्टी (AAP), भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के बीच एक शुरूआती राजनीतिक मुकाबले का मंच तैयार हो सकता है। 2022 के चुनावी नतीजों के बाद से ये सभी पार्टियाँ पंजाब में अपनी रणनीतियों को नए सिरे से तैयार कर रही हैं।

संवैधानिक प्रक्रिया और प्रक्रियात्मक बाधाएँ

बढ़ती चर्चाओं के बावजूद, चुनावों को समय से पहले करवाने के किसी भी कदम के लिए स्पष्ट संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन करना अनिवार्य होगा। 2022 के चुनावों के बाद गठित पंजाब की मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल पाँच साल का है। चुनावों को समय से पहले करवाने के लिए : राज्य मंत्रिमंडल को विधानसभा को समय से पहले भंग करने की सिफारिश करनी होगी। इस प्रस्ताव को राज्यपाल की मंजूरी मिलना अनिवार्य होगा। इसके बाद, चुनाव आयोग नए चुनावों का कार्यक्रम तय करने के लिए आगे आएगा। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि हालाँकि समय से पहले चुनाव करवाना कोई नई बात नहीं है, लेकिन ऐसे मामलों में यह बहुत कम देखने को मिलता है, जहाँ सरकार के पास स्पष्ट बहुमत हो—जैसा कि अभी पंजाब में है।

राजनीतिक प्रतिक्रियाएँ : सावधानी और सोची-समझी चुप्पी जहाँ एक ओर सत्ताधारी AAP ने इन अटकलों पर सार्वजनिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं की है, वहीं विशेषज्ञों ने इन बातों के पीछे छिपे अर्थों को समझना शुरू कर दिया है। सूत्रों का कहना है कि समय से पहले चुनाव कराना, सत्ता-विरोधी लहर (anti-incumbency) को पहले ही रोकने की एक कोशिश हो सकती है। एक वरिष्ठ नेता ने, जिन्होंने अपना नाम न बताने की शर्त पर बात की, कहा, ₹अगर सरकार को लगता है कि जमीनी हालात बदल रहे हैं, तो चुनावों को पहले कराना नुकसान को संभालने का एक तरीका हो सकता है। दूसरी ओर, BJP के भीतर कुछ लोगों को इसमें पंजाब में अपनी विस्तार योजनाओं को तेज करने का एक अवसर नजर आ रहा है। पंजाब में पार्टी अपने पुराने सहयोगी, शिरोमणि अकाली दल के कमजोर पड़ने के बाद से ही अपने संगठनात्मक आधार को मजबूत करने की कोशिश कर रही है।

इस कदम के पीछे की रणनीतिक गणनाएँ

उच्च-स्तरीय सूत्रों के अनुसार, चुनावों को पहले करवाने की संभावना पर राजनीतिक समय, शासन की छवि और राष्ट्रीय चुनावी तालमेल जैसे कई कारकों को ध्यान में रखकर विचार किया जा रहा है। चर्चाओं से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि सरकारें कभी-कभी राजनीतिक फायदे उठाने के लिए समय से पहले चुनाव करवाने का फैसला करती हैं—खासकर तब, जब उन्हें लगता है कि उनकी लोकप्रियता अपने चरम पर है। एक वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक ने कहा, ₹इसका मकसद अनिश्चितता से बचना और मतदाताओं के पास तब जाना है, जब चुनावी माहौल (नैरेटिव) अभी भी उनके नियंत्रण में हो। इस बात की भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि पंजाब के चुनावों को 2026 के आखिर में होने वाले अन्य राज्यों के चुनावों के साथ ही करवाने पर भी विचार किया जा सकता है। इस तरह के तालमेल से चुनाव आयोग के लिए चुनावी व्यवस्था (लॉजिस्टिक्स) को सुव्यवस्थित करना आसान हो जाएगा, और साथ ही राष्ट्रीय पार्टियों को भी अपने चुनावी संसाधनों को एक जगह केंद्रित करने का मौका मिलेगा।

शासन बनाम राजनीति: एक नाजुक संतुलन

विश्लेषक आगाह करते हैं कि जहाँ समय से पहले चुनाव कराने से राजनीतिक फायदे हो सकते हैं, वहीं इनमें कुछ जोखिम भी छिपे होते हैं। कार्यकाल के अचानक छोटा हो जाने से अधूरी पड़ी नीतिगत पहलों, वित्तीय योजनाओं और शासन की निरंतरता को लेकर सवाल उठ सकते हैं।

पंजाब, जो पहले से ही कर्ज, बेरोजगारी और कृषि संकट जैसी चुनौतियों से जूझ रहा है, वहाँ अगर चुनावों का समय सचमुच आगे बढ़ा दिया जाता है, तो शासन-व्यवस्था को लेकर बहस और तेज हो सकती है। चंडीगढ़ स्थित एक राजनीतिक विश्लेषक ने कहा, ₹मतदाता यह जानना चाहेंगे कि कोई सरकार अपना ही कार्यकाल समय से पहले क्यों खत्म कर रही है।

चुनाव आयोग की ओर से अभी तक कोई संकेत नहीं

भारत के चुनाव आयोग ने अब तक चुनावी कार्यक्रम में किसी भी तरह के बदलाव का कोई संकेत नहीं दिया है। अधिकारियों का कहना है कि ऐसा कोई भी फैसला तय प्रक्रियाओं के अनुसार ही लिया जाएगा और उसकी औपचारिक घोषणा की जाएगी।

विधानसभा क्षेत्र चब्बेवाल में स्थापित होगी फलों और सब्जियों की प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, 18 करोड़ रुपए की लागत से लगेगा प्रोजेक्ट

लोकसभा सांसद डॉ. राज कुमार चब्बेवाल और विधायक डॉ. इशांक कुमार ने केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान से मुलाकात की, केंद्रीय मंत्रालय ने प्रोजेक्ट को औपचारिक मंजूरी दी

दलजीत अज्नोहा

होशियारपुर/यूटर्न/01 अप्रैल। विधानसभा क्षेत्र चब्बेवाल में जल्द ही फलों और सब्जियों की प्रसंस्करण की बड़ी इंडस्ट्री स्थापित होने जा रही है। इससे कंडी और आसपास के इलाकों में फल-सब्जियों की खेती को न सिर्फ बढ़ावा मिलेगा, बल्कि किसानों की आय में भी अच्छा इजाफा होगा। लोकसभा सांसद डॉ. राज कुमार चब्बेवाल ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि विधायक डॉ. इशांक कुमार ने इस प्रोजेक्ट को लगवाने के लिए केंद्रीय मंत्रालय से संपर्क करने की मांग की थी। इसके बाद दोनों ने केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान से मुलाकात कर इस प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि करीब 18 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित होने वाला यह यूनिट आने वाले 12 महीनों में शुरू हो जाएगा। यह इलाके में फलों और सब्जियों खासकर आलू और मटर की प्रसंस्करण के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। डॉ. राज कुमार चब्बेवाल ने कहा कि होशियारपुर और आसपास

के इलाकों में फलों और सब्जियों की पैदावार की असीम संभावनाएं हैं। किसान पहले से ही इस बारे में जागरूक हैं। इस प्रोजेक्ट के लगने से फसली विविधता को बल मिलेगा और किसानों की आय में वृद्धि दर्ज की जाएगी। उन्होंने आगे बताया कि इस प्रोजेक्ट के शुरू होने से सैकड़ों लोगों खासकर महिलाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने इस यूनिट को खाद्य प्रसंस्करण और फल-सब्जियों की संरक्षण संबंधी प्रोजेक्ट्स के तहत औपचारिक मंजूरी दे दी है। डॉ. चब्बेवाल ने कहा कि यह यूनिट फलों और सब्जियों की प्रसंस्करण के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं वाला यूनिट होगा, जिससे क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हो रही मटर और आलू की खेती को भी लाभ मिलेगा। विधायक डॉ. इशांक कुमार चब्बेवाल ने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और लोकसभा सांसद डॉ. राज कुमार चब्बेवाल का धन्यवाद करते हुए कहा कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए पंजाब सरकार हर संभव मदद सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार पहले ही राज्य में निवेश के लिए बेमिसाल कदम उठा रही है और यह प्रोजेक्ट भी तय समय में पूरी प्राथमिकता के साथ शुरू किया जाएगा। इस इंडस्ट्री की स्थापना से क्षेत्र में फलों और सब्जियों की खेती को नई रफ्तार मिलेगी, जो फसली विविधता और किसानों के लिए बेहद लाभकारी साबित होगी। डॉ. इशांक कुमार ने कहा कि सभी प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए जल्द ही इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो जाएगा, ताकि आने वाले 12 महीनों के दौरान यह यूनिट तैयार हो सके और फल-सब्जियों की प्रसंस्करण को अमली जामा पहनाया जा सके।

बीच-बचाव करना पड़ा भारी, टैक्सी चालक के परिवार पर जानलेवा हमला

जीरकपुर/यूटर्न/01 अप्रैल। लोहगढ़ स्थित गोल्डन एनक्लेव में पड़ोसियों के बीच हुए विवाद में बीच-बचाव करना एक टैक्सी चालक और उसके परिवार को भारी पड़ गया। आरोप है कि पड़ोसी ने रंजिश के चलते बाहरी लोगों को बुलाकर पूरे परिवार पर लाठी-डंडों और लोहे की रॉड से जानलेवा हमला करवा दिया। इस हमले में दो युवतियों और एक गर्भवती महिला सहित कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मकान नंबर 137 निवासी मनोज कुमार ने पुलिस को बताया कि वह पेशे से टैक्सी चालक है। बीते दिनों रात के समय गली में उसके पड़ोसियों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो रहा था। शोर सुनकर वह और अन्य लोग बाहर आए और दोनों पक्षों को समझाकर शांत कर अपने-अपने घर भेज दिया। कुछ देर बाद मनोज ने देखा कि उसके पड़ोसी सुखदेव सिंह नेगी की पत्नी सुमन नेगी गली में खड़ी एक सफेद रंग की कार की ओर इशारा कर रही थी। इसी दौरान कार से 6-7 अज्ञात युवक उतरे, जिनके हाथों में डंडे और लोहे की रॉड थीं। आरोप है कि उन्होंने मनोज को उसके घर से बाहर खींचकर गली में बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। जब मनोज की पत्नी संतोष देवी और उसकी दो बेटियां उसे बचाने आईं, तो हमलावरों ने उन्हें भी नहीं बख्शा और लाठियों से हमला कर दिया। इसी बीच मनोज की छोटी भाभी कंचन उर्फ प्रेमलता जब नीचे आई, तो आरोपियों ने घर का भारी गेट उसके पेट पर दे मारा और धक्का देकर गिरा दिया। पीड़ित के अनुसार करीब 7-8 महीने पहले एक मामूली विवाद हुआ था, जिसकी रंजिश पड़ोसी के मन में थी। इसी के चलते इस हमले को अंजाम दिया गया। घटना के दौरान शोर सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हुए, जिसके बाद हमलावर जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए।

पेज 12 एसएसजीआई में 'वेक्टर ट्रैजेक्टरी' छात्र क्लब...

बिना इंटरव्यू, बिना जांच नियुक्ति पर घमासान: चंडीगढ़ में चीफ इंजीनियर की पोस्ट पर उठे गंभीर सवाल

चंडीगढ़/यूटर्न/01 अप्रैल। नगर निगम में चीफ इंजीनियर के पद पर संजय अरोड़ा की दोबारा नियुक्ति को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। बिना आवेदन, बिना इंटरव्यू और पुराने आरोपों की जांच किए बिना हुई इस नियुक्ति ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में इसे लेकर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। जानकारी के मुताबिक, जिन आरोपों के चलते पहले संजय अरोड़ा को पद से हटाया गया था, उन मामलों की जांच अब तक पूरी नहीं हुई है। इसके बावजूद उन्हें फिर से उसी पद पर बैठा दिया गया, जिससे पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। पूर्व मेयर एवं पार्षद अनूप गुप्ता ने इस फैसले की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि प्रशासन को पहले आरोपों की निष्पक्ष जांच करनी चाहिए थी। वहीं, पूर्व डिप्टी मेयर सतीश केंथ ने भी नियुक्ति प्रक्रिया पर हैरानी जताई है। उनका कहना है कि बिना जांच और चयन प्रक्रिया के किसी अधिकारी को इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देना गलत संदेश देता है। बताया जा रहा है कि इस मामले को लेकर कुछ पार्षद जल्द ही प्रशासक गुलाब चंद कटारिया से औपचारिक शिकायत करने की तैयारी में हैं।

प्रक्रिया पर उठे सवाल

सूत्रों के अनुसार, चीफ इंजीनियर पद के लिए विभिन्न राज्यों से करीब 12 अधिकारियों ने आवेदन किया था। इनमें कई उम्मीदवार योग्यता और अनुभव के मामले में मजबूत माने जा रहे थे, लेकिन किसी का इंटरव्यू तक नहीं लिया गया। ऐसे में चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।

प्रशासन की भूमिका पर भी निशाना

इस नियुक्ति को लेकर यह भी चर्चा है कि प्रशासन ने पूरी प्रक्रिया को औपचारिकता तक सीमित रखा। खास बात यह है कि पहले इसी पद पर एक्सटेंशन देने से इनकार किया गया था, लेकिन अब उसी अधिकारी की पुनर्नियुक्ति ने फैसलों की विश्वसनीयता पर भी प्रश्नचिह्न लगा दिया है। कुल मिलाकर, यह मामला अब केवल एक नियुक्ति तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि प्रशासनिक पारदर्शिता, जवाबदेही और चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता पर बड़ा सवाल बनता जा रहा है।

वार्डवासियों की समस्याओं को लेकर वार्ड 35 के पार्षद राजेंद्र शर्मा ने प्रशासक गुलाब चंद कटारिया से की भेंटवार्ता : पुनीत महाजन

चंडीगढ़/यूटर्न/01 अप्रैल। चंडीगढ़ प्रशासन से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को लेकर वार्ड नंबर 35 के पार्षद और पूर्व उप महापौर राजिंद्र शर्मा ने बुधवार को चंडीगढ़ के प्रशासक एवं पंजाब के राज्यपाल महामहिम गुलाब चंद कटारिया से उनके कार्यालय में भेंटवार्ता की और वार्डवासियों द्वारा उठायी गयी समस्याओं भरा ज्ञापन सौंपा। चंडीगढ़ के प्रशासक कटारिया से हुई भेंटवार्ता के दौरान हुई बातचीत के बारे में पार्षद राजेंद्र शर्मा ने बताया कि उन्होंने सभी समस्याओं को गंभीरता और सकरात्मक भाव से सुना और उन समस्याओं पर उचित कार्यवाही करने का आश्वासन भी दिया। वार्डवासियों की समस्याओं के बारे में शर्मा ने बताया कि उनके वार्ड में अधिकाँश तौर पर विभिन्न सोसाइटीज के फ्लैट हैं। इसमें कई सोसाइटीज को 20 वर्षों से ऊपर हो गए अभी तक एस्टेट ऑफिस द्वारा पूर्णता प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है दूसरा सेक्टर 50 में चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा विभिन्न प्रोजेक्ट्स के लिए अलाट की जाने वाली भूमि गत 25 वर्षों से खाली रहने से वहां जंगल बन गया है वो स्थल महिलाओं आदि के लिए सुरक्षित नहीं रहा है स्थानीय लोगों ने मांग की है कि उस जमीन पर एक तो उनको मार्किट उपलब्ध करवाई जाए दूसरा खाली पड़ी जमीन पर साफ सफाई की जायें इस सेक्टर में कोई मार्किट न होने की वजह से रोजमर्रा की जरूरतों के लिए वहां के निवासियों को अन्य सेक्टर की मार्किट में जाने को विवश होना पढ़ता है इसके अलावा कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज के लोगों द्वारा उनके की गयी नीड बेस चेंज को चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के निवासियों की तर्ज पर नियमित करने , इसके अलावा उन्होंने चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया को बताया कि उनके घरों को लीज होल्ड तो फ्री होल्ड करने में लगाए जाने वाले चार्जेज को भी कम किया जाए चूँकि यहाँ के निवासी जयादातर रिटायर्ड पेंशनर्स और वरिष्ठ नागरिक हैं जिनको अपनी पेंशन के भीतर ही सीमित मात्रा में खर्चा करना होता है। उन्होंने बताया कि प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने पार्षद शर्मा द्वारा स्थानीय लोगों की समस्याओं को गंभीरता से लिया और अपने अधिकारीयों को इस से सम्बंधित विभागों के अधिकारीयों से बात करने को कहा ताकि उपरोक्त समस्याओं को हल करवाने हेतु इसके लिए यथासंभव हल निकाला जा सके उनके आश्वासन पर पार्षद राजिंदर शर्मा ने प्रशासक गुलाब चंद कटारिया का आभार व्यक्त किया।

एफ एंड सीसी बैठक में हंगामा: पार्षद बंटी ने अफसरों पर मनमानी और कर्मचारियों के दुरुपयोग के लगाए आरोप

चंडीगढ़/यूटर्न/01 अप्रैल। नगर निगम की 30 मार्च को हुई फाइनेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट कमेटी (एफ एंड सीसी) की बैठक में उस वक्त तीखी बहस छिड़ गई जब पार्षद जसबीर सिंह बंटी ने अधिकारियों की कार्यशैली पर गंभीर आरोप जड़ दिए। बैठक का माहौल आरोप-प्रत्यारोप के बीच गर्म रहा। पार्षद बंटी ने कहा कि रोड डिवीजन नंबर-1 के तीन कर्मचारियों को बिना ठोस कारण के डिवीजन नंबर-2 में शिफ्ट कर दिया गया, जिससे उनके वार्ड में चल रहे विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने इसे प्रशासनिक मनमानी करार दिया।

उन्होंने आरोप लगाया कि जसप्रीत सिंह (एमटीएस) को संबंधित अधिकारी निजी कार्यों में इस्तेमाल कर रहे हैं। बंटी के अनुसार, एसडीओ उन्हें अपने साथ ले जाकर गाड़ी चलवाने जैसे निजी काम करवा रहे हैं, जो नियमों का उल्लंघन है। बैठक में चरणप्रीत सिंह के कार्यक्षेत्र को लेकर भी सवाल उठे। पार्षद ने बताया कि उनकी ड्यूटी आर-6 क्षेत्र में थी, लेकिन वे आर-10 में काम कर रहे थे। इस पर अधिकारियों ने स्वीकार किया कि वह वहां 'अनधिकृत रूप से' कार्य कर रहे थे, हालांकि यह स्पष्ट नहीं किया गया कि इसके पीछे किसका आदेश था। इस दौरान एक अधिकारी के बयान कर्मचारियों को जहां चाहें तैनात कर सकते हैं ना विवाद को और बढ़ा दिया। पार्षद बंटी ने इसे जवाबदेही की कमी और नियमों की अनदेखी बताया।

उन्होंने यह भी कहा कि कर्मचारियों के ट्रांसफर के बाद उनके वार्ड में कई जरूरी काम अटक गए हैं, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पार्षद ने मेयर से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। साथ ही यह भी सवाल उठाया कि बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली लागू होने के बावजूद इस तरह की अनियमितताएं कैसे हो रही हैं। अंत में बंटी ने चेतावनी दी कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई, तो इस मुद्दे को बड़े स्तर पर उठाया जाएगा।

बापूधाम-राम दरबार में नशे के कारोबार पर कांग्रेस का हमला, वेंडर जोन मुद्दे भी उठाए

चंडीगढ़/यूटर्न/01 अप्रैल। चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता कृष्ण लाल और पूर्व मेयर कमलेश बनारसीदास ने बुधवार को पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया से सचिवालय में मुलाकात कर शहर की कानून-व्यवस्था और वेंडरों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया।

प्रतिनिधिमंडल ने आरोप लगाया कि बापूधाम और राम दरबार क्षेत्रों में पुलिस की कथित मिलीभगत से खुलेआम नशे का कारोबार चल रहा है। उन्होंने कहा कि इन इलाकों में अपराध बढ़ते जा रहे हैं, आए दिन झगड़े और चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे लोगों में असुरक्षा का माहौल है।

कांग्रेस नेताओं ने वेंडरों की समस्याओं को भी विस्तार से रखा। उनका कहना था कि जिन वेंडरों का सर्वे कर उन्हें वैध रूप से लाइसेंस दिया गया है, उन्हें ऐसे वेंडर जोन आवंटित किए गए हैं जो उनके मूल कार्यस्थल से काफी दूर हैं। इन स्थानों पर ग्राहकों की कमी के चलते उनकी आजीविका पर गंभीर असर पड़ा है और कई परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि कई बुजुर्ग वेंडर दूरी के कारण निर्धारित वेंडर जोन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। साथ ही वहां रात्रि ठहराव की भी कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे उनकी परेशानी और बढ़ जाती है। नेताओं ने मांग की कि वेंडर जोन वहीं बनाए जाएं, जहां उनका मूल सर्वे हुआ था। सेक्टर-26 स्थित ग्रेन मार्केट का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कहा कि कई वेंडर वर्षों से लाइसेंस शुल्क जमा कर रहे हैं और उनका सर्वे भी वहीं हुआ था, बावजूद इसके उन्हें वहां बैठने की अनुमति नहीं दी जा रही।

मुलाकात के दौरान बापूधाम और राम दरबार में समाधान शिविर लगाने की मांग भी रखी गई, जिस पर प्रशासक ने इन क्षेत्रों में जल्द शिविर आयोजित करने का आश्वासन दिया। प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने सभी मुद्दों को गंभीरता से सुनते हुए शीघ्र समाधान का भरोसा दिलाया।

श्री शारदा माता मंदिर में चतुर्दशी भंडारे का आयोजन

नए शिवालय का नींव पत्थर रखा गया, श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़

डेराबस्सी/यूटर्न/01 अप्रैल। साधुनगर स्थित श्री शारदा माता मंदिर में वार्षिक चतुर्दशी भंडारे का आयोजन श्रद्धा एवं भक्ति भाव के साथ किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने उपस्थित होकर माता रानी के चरणों में शीश नवाया और धार्मिक कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम में विशेष रूप से सरदार गुरदर्शन सिंह ने हाजिरी लगवाई तथा नए शिवालय के निर्माण हेतु नींव पत्थर रखा गया। मंदिर प्रबंधक समिति श्री शारदा माता परिवार 7249 के प्रधान राकेश अचिंत ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी चतुर्दशी भंडारे का

आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई। उन्होंने बताया कि सरदार गुरदर्शन सिंह एवं मंदिर कमेटी के सरपरस्त सरदार अमृतपाल सिंह मोदी के सहयोग से शिव मंदिर का नींव पत्थर पंडित दीपक शास्त्री द्वारा विधिवत पूजन कर रखवाया गया। इसके पश्चात मंदिर की कीर्तन मंडली द्वारा महामाई का गुणगान किया गया और श्रद्धालुओं में प्रसाद वितरित किया गया। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता सरदार गुरदर्शन सिंह सैनी, हरप्रीत सिंह टिंकू (प्रधान, ओबीसी मोर्चा), श्रुति भारद्वाज (उपाध्यक्ष, जिला मोहाली), समाजसेवी कृष्णा सूद सहित मंदिर के चेयरमैन राकेश मेहता, उपप्रधान दीपक मग्गो, कोषाध्यक्ष कुनाल कौशिक, सचिव रजनीश शर्मा, तुषार कौशिक, भुवनेश चौहान, संदीप भटनागर, रवि बावा, शुभम बावा, विकास शर्मा, प्रकाश कुमार, सुमित वर्मा, राघव गोयल, सुमित पुरी, दिनेश गांधी, जतिन धीमान सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे। इसके अलावा कीर्तन मंडली की सदस्य सपना मेहता, सपना गोयल, सुनीता कौशिक, जोली, ज्योति, सीमा कालरा, सुनीता, सीमा, शशि सहित अनेक श्रद्धालु कार्यक्रम में मौजूद रहे।

माता शीतला मंदिर का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया

डेराबस्सी/यूटर्न/01 अप्रैल। गांव हरिपुर कूड़ा में माई शीतला माता मंदिर का स्थापना दिवस श्रद्धा और उत्साह के साथ धूमधाम से मनाया गया। इस पावन अवसर पर बाबा सबल सिंह, बाबा रेपा चौधरी, बाबा फरीद एवं माता स्याम कौर जी की मूर्तियों की विधिवत स्थापना की गई। समारोह में भाजपा नेता मनप्रीत सिंह (बन्नी) मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जबकि भाजपा मंडल अध्यक्ष पवन धीमान (पम्मा) भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि ने मंदिर समिति को इस आयोजन के लिए बधाई देते हुए कहा कि ऐसे धार्मिक कार्यक्रम समाज में एकता और भाईचारे को मजबूत करते हैं। मंदिर समिति के प्रधान गुरमीत सिंह ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए बताया कि गांववासियों के सहयोग से कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस अवसर पर कृष्ण धीमान, जयपाल, राजेश कुमार (मंगू), लखविंदर सिंह, कृष्ण सिंह, अमन पाहवा, प्रदीप कुमार (लाडी), गुरविंदर सिंह, मनीष, राजेश, रसविंदर सिंह, जसवीर सिंह, निखिल, चरणजीत, अर्शदीप, निखलजीत सिंह सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण एवं महिलाएं उपस्थित रहीं।

रूह से रूबरू

चारू नागपाल

एक नेता जिसने दुनिया को भीख का कटोरा पकड़ा दिया।

डोनाल्ड ट्रम्प को अक्सर एक बेबाक और विवादित नेता के रूप में देखा जाता है। उनकी भाषा और फैसलों ने कई बार दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। कुछ लोगों का मानना है कि उनकी नीतियों ने वैश्विक स्तर पर अस्थिरता पैदा की, जिससे कई देशों को आर्थिक और राजनीतिक दबाव का सामना करना पड़ा। इसी कारण यह धारणा भी बनी कि दुनिया जैसे ₹भीख का कटोरा₹ लेकर खड़ी हो गई है, हालांकि यह एक भावनात्मक अभिव्यक्ति है।

ट्रंप के कार्यकाल में अंतरराष्ट्रीय संबंधों में तनाव बढ़ा, खासकर बड़े देशों के बीच। व्यापार युद्ध, कड़े बयान और सैन्य शक्ति का प्रदर्शन-इन सबने दुनिया को World War III जैसी आशंकाओं के करीब ला खड़ा कर दिया है उन्होंने पूरी दुनियाभर में डर और अनिश्चितता का माहौल जरूर बना दिया। उनके गलत फैसले में नाटो में उनके अति सहयोगी देश इटली, स्पेन और फ्रांस आदि ने भी उनका साथ देने से इंकार कर दिया। कुछ लोग उन्हें एक ऐसा नेता मानते हैं जिसने टकराव की राजनीति को बढ़ावा दिया, जबकि अन्य लोग मानते हैं कि उन्होंने अपने देश के हितों को सबसे ऊपर रखा। इस तरह, ट्रंप की छवि कुछ के लिए मजबूत नेता की है, तो कुछ के लिए विवादों का कारण।

अंत में, यह कहना उचित है कि उनके नेतृत्व ने दुनिया में बहस और विभाजन दोनों को जन्म दिया, और उनकी नीतियों का असर आज भी चर्चा का विषय बना हुआ है।

कानूनी बात - निशांत प्रभाकर के साथ

निशांत प्रभाकर, एडवोकेट

Lis Pendens: मुकदमे के दौरान संपत्ति बेचने का क्या प्रभाव होता है?

कई बार ऐसा होता है कि किसी संपत्ति को लेकर अदालत में मुकदमा चल रहा होता है, और उसी दौरान मालिक उस संपत्ति को किसी तीसरे व्यक्ति को बेच देता है। ऐसे मामलों में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत लागू होता है—Lis Pendens.

सरल शब्दों में, Lis Pendens का अर्थ है—जब किसी संपत्ति पर विवाद अदालत में लंबित हो, तो उस दौरान किया गया लेन-देन उस मुकदमे के परिणाम के अधीन रहेगा। यानी बिक्री पूरी तरह अवैध नहीं होती, लेकिन खरीदार उस संपत्ति को 'जोखिम' के साथ खरीदता है। इसका मतलब यह है कि यदि बाद में अदालत किसी अन्य पक्ष के पक्ष में फैसला देती है, तो खरीदार को भी उसी निर्णय को मानना पड़ेगा। वह यह नहीं कह सकता कि उसने संपत्ति 'अच्छी नीयत' से खरीदी थी, इसलिए उस पर फैसला लागू नहीं होगा।

Lis Pendens का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मुकदमे के दौरान कोई पक्ष संपत्ति बेचकर या हस्तांतरित करके न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित न कर सके। इससे स्थिति स्थिर बनी रहती है और अदालत का अंतिम निर्णय प्रभावी रहता है। यह भी समझना जरूरी है कि Lis Pendens स्वतः लागू होता है—इसके लिए अलग से आदेश की आवश्यकता नहीं होती। जैसे ही संपत्ति पर मुकदमा लंबित होता है, यह सिद्धांत सक्रिय हो जाता है। इसलिए संपत्ति खरीदते समय यह जाँच करना अत्यंत आवश्यक है कि उस पर कोई मुकदमा लंबित तो नहीं है। अन्यथा खरीदार अनजाने में लंबे विवाद में फँस सकता है।

निष्कर्ष : Lis Pendens खरीदार को सावधान करता है कि लंबित विवाद वाली संपत्ति जोखिम के साथ आती है। मुकदमे के दौरान की गई बिक्री अंतिम अधिकार नहीं देती—वह अदालत के निर्णय के अधीन रहती है। सुरक्षित खरीद के लिए विवाद की स्थिति की जाँच अनिवार्य है।

विश्रांति सिटी में हेल्थ कैंप में उमड़ी भीड़, 100 से अधिक हेल्थ कार्ड बने

मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत लोगों को मिली बड़ी राहत

जीरकपुर/यूटर्न/01 अप्रैल। शहर के गाजीपुर रोड स्थित विश्रांति सिटी में मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत आयोजित विशेष हेल्थ कैंप में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह 9 बजे शुरू हुआ यह कैंप शाम 4 बजे तक लगातार चलता रहा, जिसमें दिनभर लोगों की आवाजाही बनी रही।

कैंप का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं से जोड़ना और उन्हें हेल्थ कार्ड जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना था। इस दौरान 100 से अधिक लोगों के हेल्थ कार्ड बनाए गए, जिससे उन्हें भविष्य में सरकारी एवं संबद्ध अस्पतालों में उपचार के दौरान आर्थिक सहायता मिल सकेगी।

कैंप में केवल विश्रांति सिटी ही नहीं, बल्कि आसपास के क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। गाजीपुर रोड, माउंट कैलाश सोसाइटी, बाजीगर बस्ती और नगला क्षेत्र के निवासियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर अपने हेल्थ कार्ड बनवाए। कई लोग सुबह से ही लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए, जो योजना के प्रति बढ़ती जागरूकता को दर्शाता है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि इस प्रकार के कैंप उनके लिए अत्यंत लाभकारी हैं, क्योंकि अब उन्हें हेल्थ कार्ड बनवाने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। मौके पर मौजूद टीम ने दस्तावेजों की जांच और पूरी प्रक्रिया को सरल बनाया, जिससे लोगों को बिना किसी परेशानी के सुविधा का लाभ मिला। इस अवसर पर आम आदमी पार्टी के वार्ड नंबर 17 से ब्लॉक कोऑर्डिनेटर मनीष कुमार, वार्ड इंचार्ज जसविंदर सिंह, विश्रांति सिटी के प्रधान राजेंद्र शर्मा सहित रामेश्वर, रामचंद्र, भले राम, सुभाष, महेश चंद्र और पारस कटारिया मौजूद रहे। सभी ने कैंप के सफल संचालन में सहयोग देते हुए लोगों को योजना के प्रति जागरूक किया। आयोजकों ने बताया कि भविष्य में भी इस प्रकार के कैंप आयोजित किए जाएंगे, ताकि अधिक से अधिक लोग सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ उठा सकें। वहीं, स्थानीय लोगों ने प्रशासन से ऐसे कैंप नियमित रूप से लगाने की मांग की है, जिससे हर जरूरतमंद तक स्वास्थ्य सुविधाएं आसानी से पहुंच सकें।

नाबालिग लड़की लापता, युवक पर भगाने का आरोप

जीरकपुर/यूटर्न/01 अप्रैल। ढकोली थाना क्षेत्र से एक नाबालिग लड़की के लापता होने का मामला सामने आया है। परिजनों ने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर निवासी एक युवक पर शादी का झांसा देकर लड़की को बहला-फुसलाकर भगाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिकायतकर्ता के अनुसार उनकी 17 वर्षीय भतीजी पिछले 8-9 महीनों से उनके पास रह रही थी और पंचकूला के सेक्टर-14 स्थित आईटीआई में ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर रही थी। 23 मार्च 2026 को वह रोजाना की तरह प्रशिक्षण के लिए घर से निकली, लेकिन शाम तक वापस नहीं लौटी। परिजनों ने अपने स्तर पर काफी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। जब प्रशिक्षण केंद्र में संपर्क किया गया तो पता चला कि लड़की उस दिन वहां पहुंची ही नहीं थी।

अवैध बिल्डिंग मालिकों के पास जादू की छड़ी ! जो अधिकारी कार्रवाई करने गया, वहीं हो गया शांत

चर्चा; कई अधिकारियों ने बनवा रखे हैं कि अनरिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटियों के सर्टीफिकेट

लुधियाना/यूटर्न/1 अप्रैल। नगर निगम जोन-ए में अवैध इमारतों का लगातार बोलबाला बढ़ता जा रहा है। हालात यह है कि एक के बाद एक इमारत बन रही है या बनकर तैयार हो चुकी है। मगर शिकायतें मिलने और मौका विजिट करने के बावजूद बिल्डिंग ब्रांच के अधिकारी कार्रवाई करने में असमर्थ नजर आ रहे हैं। हाल ही में अधिकारियों के ट्रांसफर होने के बाद नए एटीपी और इंस्पेक्टरों द्वारा चार्ज संभाला गया है। जिनकी और से पुराने अधिकारियों द्वारा इमारतें बनवाने के आरोप लगाए जा रहे हैं। बेशक इमारतें पुराने अफसरों ने बनवाई, लेकिन वह मौजूदा अधिकारी होने के बावजूद भी कौन सा एक्शन ले पा रहे हैं। जोन-ए के अधीन आती पुरानी कोतवाली एरिया और चांद सिनेमा रोड पर अवैध इमारतें बनी, वहीं भदौड़ हाउस और शू मार्केट के पास पांच अवैध होटल बने। जहां पर बिल्डिंग ब्रांच के अफसर कार्रवाई करने जरुर गए, लेकिन कहीं अधूरी कार्रवाई की और कहीं बिना एक्शन के वापिस लौट आए। ऐसे में शहर में चर्चा छिड़ गई है कि आखिर इललीगल इमारतों के मालिकों के पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है कि अधिकारी पूरे जोश के साथ कार्रवाई करने जाते हैं, लेकिन वहां जाकर कार्रवाई किए बिना शांत होकर वापिस आ जाते हैं। आखिर बिल्डिंग मालिक ऐसा कौन सा जादू करते हैं, जिससे अधिकारी एक्शन लेना ही भूल जाते हैं।

पुरानी कोतवाली एरिया में बनी अवैध इमारत

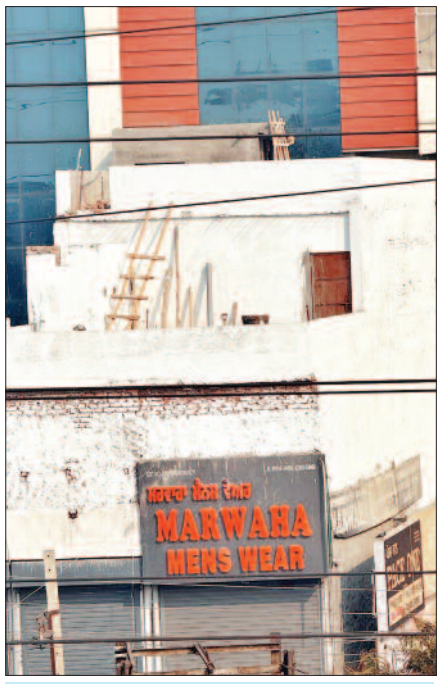

चांद सिनेमा रोड पर बनाई अवैध मंजिलें

अधिकारियों को कार्रवाई के लिए कहा

एमटीपी विजय कुमार ने बताया कि सभी जोन के बिल्डिंग ब्रांच अधिकारियों को हर अवैध इमारत पर कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। इन मामलों संबंधी भी उनसे रिपोर्ट मांगी जाएगी।

कई यूनिवर्सिटी अनरिकॉग्नाइज्ड घोषित

बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा कई यूनिवर्सिटी और कॉलेज को अनरिकॉग्नाइज्ड घोषित कर रखा है। यह वह संस्थान हैं, जिनकी और से बिना बच्चों को पढ़ाए, सीधे रिश्वत लेकर सर्टीफिकेट जारी कर दिए जाते थे। जिनकी पहचान करने के बाद सरकार द्वारा इन्हें ब्लैक लिस्ट कर दिया गया था। वहीं एक्सपर्ट की मानें, तो उनका कहना है कि अगर अधिकारियों द्वारा गलत तरीके से सर्टीफिकेट बनवा रखे हैं तो उनकी जरुर जांच होनी चाहिए। क्योंकि ऐसे अधिकारी सही तरीके से काम करके कैसे शहर को सुंदर बना सकेगें।

एक्शन लेना तो दूर, बात करना पसंद नहीं करते

वहीं शहर में चर्चा है कि अधिकारियों द्वारा पहले पूरे जोश के साथ कार्रवाई करने का ऐलान किया जाता है। यहीं नहीं, वह मौके पर कार्रवाई करने के लिए भी जाते हैं, लेकिन बाद में एकदम ऐसे बदलाव आता है कि वह कार्रवाई करना तो दूर उक्त इमारत की बात तक करना पसंद नहीं करते। जिसके चलते उच्च अधिकारियों को इसकी जांच करनी चाहिए कि आखिर ऐसे क्या होता है कि नीचले सत्र के अफसर कार्रवाई नहीं कर पाते। क्या उन पर कोई राजनीतिक दबाव होता है।

पहले इंस्पेक्टर कशिश, फिर मक्कड़, एक्शन लेने से पीछे हुए

पहले मामले में पुरानी कोतवाली एरिया में पीएस मोबाइल स्पेयर पॉट्स के नाम से मोबाइल असेंसरी शोरुम बेसमेंट समेत छह मंजिलां बना डाला, जबकि वह दो मंजिल पास है। मामले में 24 फरवरी को पूर्व इंस्पेक्टर कशिश गर्ग द्वारा बिल्डिंग मालिक को नोटिस निकाला। उसके बाद रिकॉर्ड इंस्पेक्टर हरमिंदर सिंह मक्कड़ द्वारा न देने की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया। मैडम गर्ग खुद मानी कि बिल्डिंग अवैध है और सील होगी। फिर मालिक निगम ऑफिस अफसरों से मिले और मामला शांत हो गया। फिर कशिश गर्ग छुट्टी पर चली गई, तो इंस्पेक्टर हरमिंदर सिंह मक्कड़ ने चार्ज संभाला। इंस्पेक्टर मक्कड़ पांच दिन पहले दस्तावेज देखने और कार्रवाई करने शोरुम पहुंचे। मगर मालिक से बातचीत करके वापिस लौट आए। आज तक न तो बिल्डिंग सील हुई और न ही इंस्पेक्टर मक्कड़ उक्त मामले की कार्रवाई का जवाब दे रहे हैं। हर अधिकारी जांच की बात कहकर टाल देता है।

मरवाहा मैन्स वेयर की बिल्डिंग पर बड़ा हाथ

वहीं चांद सिनेमा रोड पर मरवाहा मैन्स वेयर नाम से गारमेंट शोरुम बना। इस संबंधी पूर्व कमिश्नर आदित्य डेचलवाल और एडिशनल कमिश्नर परमदीप सिंह खैरा द्वारा उस समय एटीपी को कार्रवाई के आदेश दिए। मगर एक्शन न लिया तो विभाग ने तबादला कर एटीपी जगदीप सिंह को कमान सौंपी और एक्शन के आदेश दिए। लेकिन एटीपी जगदीप ने बिल्डिंग मालिक को दस्तावेज लेकर बुलाया और उसके बाद आज तक एक्शन नहीं हुआ। नए अधिकारियों ने अभी कार्रवाई का सोचा नहीं। वहीं भदौड़ हाउस के होटल सरताज, विक्रांत, ग्रेट वाल, महाराजा और शू मार्केट नजदीक होटल नीलकंठ की इमारतें पूरी तरह से अवैध होने के बावजूद अफसरों ने कुछ कमरे अवैध बता सील किए।

चर्चा: इंस्पेक्टर मक्कड़ के पास अनरिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी का डिपलोमा सर्टीफिकेट

वहीं, चर्चा है कि मौजूदा समय में जोन-ए में बिल्डिंग इंस्पेक्टर नियुक्त हरमिंदर सिंह मक्कड़ के पास सिविल इंजीनियरिंग का डिपलोमा सर्टीफिकेट अनरिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी का है। उसी डिपलोमा सर्टीफिकेट के आधार पर उन्हें विभाग की और से इंस्पेक्टर नियुक्त किया हुआ है। हालांकि उनके इस सर्टीफिकेट खिलाफ डायरेक्टर लोकल बॉडी विभाग को शिकायतें भी हुई। जिसके चलते विभाग द्वारा इस संबंधी रिपोर्ट भी बनाई गई है। लेकिन चर्चा है कि उक्त रिपोर्ट पर एक्शन नहीं हो सका। चचार्ए यह भी है कि इसके अलावा भी निगम के कई अन्य अधिकारी विभाग में अनरिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटियों के सर्टीफिकेट देकर भर्ती हुए या तरक्कियां ली हैं। जिसके चलते विभाग को इसकी जांच गहनता से करके सच सामने लाना चाहिए।

नगर निगम में मेट भर्ती हुए थे इंस्पेक्टर मक्कड़

जानकारी के अनुसार इंस्पेक्टर हरमिंदर सिंह मक्कड़ के पिता स्वर्गीय सतनाम सिंह नगर निगम में पहले मेट के पद पर तैनात थे। बेलदार से ऊपर की पोस्ट मेट की होती है। जिसका कार्य लेबर से काम कराना होता है। चर्चा है कि नौकरी पर तैनाती के कार्यकाल के दौरान पिता सतनाम सिंह की मौत हो गई। जिसके बाद डेथ केस होने के चलते उनकी जगह हरमिंदर मक्कड़ को मेट की नौकरी मिल गई। करीब 15 साल पहले वह निगम में भर्ती हुए थे। चर्चा है कि 2016 में हरमिंदर मक्कड़ द्वारा सिविल डिपलोमा दिखाकर इंस्पेक्टर का पद गृहण किया गया।

तीन साल का होता है डिपलोमा

वहीं बता दें कि सिविल इंजीनयरिंग की डिग्री चार साल की और डिपलोमा तीन साल का होता है। किसी भी व्यक्ति ने डिग्री या डिपलोमा करना हो तो उसके लिए कॉलेज रेगुलर जाना जरुरी होता है, क्योंकि उसमें हाजरी लगनी जरुरी होती है।

शिफारिशियों को राहत, आम जनता को सीलिंग

कारपोरेशन में दोहरी राजनीति अपनाई जा रही है। जिसमें शिफारिशियों को राहत दी जा रही है। जबकि आम जनता पर एक्शन लिया जा रहा है। ऐसा ही कुछ इन मामलों में देखने को मिला। जिसमें इन अवैध इमारतों पर तो एक्शन नहीं लिया, जबकि भदौड़ हाउस में बनी पाँच मंजिला इमारत मालिक की शिफारिश ना होने पर उसे सील कर दिया गया। शहरवासियों का कहना है कि या तो निगम सभी पर एक्शन ले, नहीं तो आम जानता को भी राहत दे।

मंत्री के दरबार में पहुंचा मामला

वही चर्चा है की कहीं यह विपक्ष को मुद्दा देने और आप पार्टी को बदनाम करने की साजिश तो नहीं हो रही। क्यूंकि जल्द चुनाव है, और यह गलत कार्य कहीं ना कहीं विपक्ष का मुद्दा बन सकते है। ऐसे में आप सरकार और मंत्री संजीव अरोड़ा को इस मामले में संज्ञान लेने की जरूरत है। वही चर्चा है कि यह मामला मंत्री के दरबार में पहुंच चुका है। जल्द मामले में एक्शन हो सकता है।

शिकायत, नोटिस और अफसरों के आदेश के बावजूद मार्किट कमेटी ने नहीं की कार्रवाई, अधिकारियों की कार्यशैली पर उठे सवाल

मिलन

लुधियाना/यूटर्न/1 अप्रैल। महानगर के बहादुरके रोड़ नजदीक स्थित दाना मंडी में इंडस्ट्रियल रबर पैड्स और रबर शीट्स का अवैध भंडारण एक महीने से अधिक समय बीतने के बाद भी नहीं हटाया गया है। शिकायत दर्ज होने, नोटिस जारी किए जाने और उच्च अधिकारियों द्वारा मार्किट कमेटी के अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश देने के बावजूद मौके पर स्थिति जस की तस बनी हुई है, जिससे अब पूरे सिस्टम की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। जानकारी के अनुसार इस मामले में पंजाब मंडी बोर्ड मुख्यालय के सेक्रेटरी तथा न्यू मंडी टाउनशिप के डायरेक्टर ऑफ कॉलोनाइजेशन द्वारा कार्रवाई करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद स्थानीय स्तर पर मार्केट कमेटी, सलेम टाबरी के अधिकारियों द्वारा कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया। मौके की ताजा स्थिति यह दशार्ती है कि अवैध रूप से रखा इंडस्ट्रियल रबर अब भी वहीं पड़ा हुआ है। जिसके चलते चर्चाएं हैं कि शायद अधिकारियों की और से आपसी मिलीभगत के चलते कार्रवाई नहीं की जा रही।

नोटिस जारी, लेकिन कार्रवाई शून्य

स्थानीय लोगों का कहना है कि संबंधित विभाग द्वारा केवल नोटिस जारी कर औपचारिकता पूरी कर दी गई, जबकि जमीनी स्तर पर कोई बदलाव नहीं हुआ। इससे यह सवाल उठ रहा है कि क्या कार्रवाई को जानबूझकर टाला जा रहा है, जबकि इंडस्ट्रियल रबर का यह भंडारण रिहायशी क्षेत्र और खाली प्लॉट्स तक फैल चुका है। इससे गंदगी, बदबू और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ रही हैं। साथ ही आग लगने की स्थिति में बड़े हादसे का खतरा बना हुआ है, जिससे स्थानीय लोग लगातार चिंता में हैं।

कथित सेटिंग को लेकर भी हो रही चर्चा

मामले में लगातार हो रही देरी को लेकर अब क्षेत्र में कथित सेटिंग की चर्चा भी जोर पकड़ने लगी है। स्थानीय स्तर पर यह सवाल उठाया जा रहा है कि इतना समय बीतने, शिकायत, नोटिस और उच्च अधिकारियों के निदेर्शों के बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। कुछ सूत्रों का कहना है कि लंबे समय से चल रही इस गतिविधि के कारण संबंधित स्तर पर ढील बरती जा रही है, जिससे अब कार्रवाई पर संदेह के बादल और गहरे हो गए हैं। इसके साथ ही यह भी चर्चा में है कि संबंधित पक्षों के बीच नजदीकी या जान-पहचान होने के कारण भी कार्रवाई में देरी हो रही है। हालांकि इन दावों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन मौजूदा हालात ने कई सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं।

अधिकारियों की जवाबदेही तय करना जरुरी

स्थानीय निवासियों ने पंजाब मंडी बोर्ड के उच्च अधिकारियों से मांग की है कि इस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका स्पष्ट की जाए और यह बताया जाए कि आदेशों और नोटिस के बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं हुई। लोगों का कहना है कि यदि जल्द सख्त कदम नहीं उठाए गए, तो मामला उच्च स्तर तक उठाया जाएगा। जिसके चलते दाना मंडी का यह मामला अब केवल अवैध भंडारण तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह प्रशासनिक कार्यप्रणाली और जवाबदेही की परीक्षा बन चुका है। अब देखना यह है कि क्या सलेम टाबरी मार्किट कमेटी वास्तविक में कार्रवाई करते हैं या मामला केवल कागजी नोटिस तक ही सीमित रहता है।

दो महीने पहले हुई थी शिकायत

इस मामले को लेकर पहले ही इलाका निवासियों द्वारा फरवरी के महीने पंजाब मंडी बोर्ड के सेक्रेटरी को लिखित शिकायत दर्ज की जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी हालात में कोई सुधार नहीं हुआ है।

नोटिस के बाद भी कार्रवाई न होना गंभीर लापरवाही - एडवोकेट सुभद्रा

एडवोकेट सुभद्रा ने कहा कि जब किसी अवैध गतिविधि पर नोटिस जारी हो चुका हो और उसके बाद भी कार्रवाई न हो, तो यह प्रशासनिक जिम्मेदारी निभाने में कमी को दशार्ता है। रिहायशी इलाके में इंडस्ट्रियल रबर का भंडारण कानून के खिलाफ है और इस पर तुरंत प्रभावी कार्रवाई की जानी चाहिए। यदि संबंधित अधिकारी कार्रवाई नहीं करते, तो उनकी जवाबदेही भी तय की जानी चाहिए।

किन्नरों के दो गुटों में झड़प, जान से मारने की दी धमकी

लुधियाना/यूटर्न/1 अप्रैल। रंजीत एवेन्यू फेज-2 इलाके में किन्नर समुदाय के दो गुटों के खूनी झड़प हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि मारपीट और हथियारों तक पहुंच गया। आरोप है कि एक गुट ने दूसरे गुट को घेरकर तेजदार हथियारों से हमला किया और जान से मारने की धमकियां दीं। थाना डेहलों की पुलिस ने इस मामले में जांच के बाद 6 आरोपियों के खिलाफ नाम सहित और 5 से 6 अज्ञात लोगों पर ऋक्षफदर्ज की। शिकायतकर्ता रिश्का सिंह महंत ने बताया कि 30 मार्च को वह अपने गुरु भाइयों के साथ गाड़ियों में सवार होकर रंजीत एवेन्यू फेज-2 स्थित एक विवाह वाले घर में बधाई लेने गए थे। इस दौरान वहां पहले से मौजूद दूसरी पार्टी के सदस्य छोटी महंत, रूही महंत, सलोनी महंत, सोना मरासी, गुलजार मरासी, टोनी मरासी और 5-6 अज्ञात व्यक्ति भी गाड़ियों में पहुंचे। आरोप है कि उन्होंने आते ही गाली-गलौच शुरू कर दी। स्थिति बिगड़ती देख वह लोग मौके से निकलकर मेन सड़क पर आ गये, लेकिन आरोपियों ने उनका पीछा कर रास्ते में घेर लिया। इसके बाद आरोपियों ने हमला कर दिया। साथ ही जान से मारने की धमकियां भी दी गई। पुलिस को दी शिकायत में आरोपियों की पहचान कर ली गई है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।

वार्ड-92 में बैडमिंटन कोर्ट व पार्क के सौंदर्यकरण का विधायक बग्गा ने किया उदघाटन

लुधियाना/यूटर्न/1 अप्रैल। विधानसभा उतरी के वार्ड 92 स्थित इंद्र विहार व प्रीतम नगर में पार्क के सौंदर्यकरण व बैडमिंटन कोर्ट का उदघाटन विधायक चौधरी मदन लाल बग्गा ने स्थानीय लोगों की उपस्थिति में किया। क्षेत्र में बैडमिंटन कोर्ट युवा पीढ़ी को खेल गतिविधियो में व्यस्त रखकर नशे से दूर रखने में मददगार साबित होगा। इस प्रोजैक्ट पर करीब 13.5 लाख रुपये की लागत आएगी। इस अवसर पर पार्षद बिट्टू भारदवाज, गौरव बग्गा भी उपस्थित रहे। विधायक बग्गा ने विधानसभा उतरी के पहले से बने खेल पार्को का जिक्र करते हुए कहा इससे पूर्व सलेम टाबरी, जालंधर बाईपास चौंक सहित अनेक स्थलो खेल पार्क निर्मित किए गए हैं। जिसमें प्रतिदिन युवा पीढ़ी प्रैक्टिस करके जिला, प्रदेश व राज्य स्तर के खिलाड़ियो की प्रतिभा को निखार रही है। बैडमिंटन कोर्ट के साथ-साथ पार्क के सौंदर्यकरण के शुरू हुए कार्यो पर उन्होंने कहा लगभग दो दर्जन स्थलों पर नए पार्को के निर्माण सहित पुराने पार्को का सौंदर्यकरण किया जा रहा है। इस पार्क में बच्चो के खेलने के लिए भी विशेष व्यवस्था होगी। इस अवसर पर महिला विंग अध्यक्ष मनीषा कपूर, विधानसभा को-आर्डिनेटर पूनम अरोड़ा, शिवांगी धीमान, पिंकी बंगा, मनोमहन सिंह, रमेश शुक्ला, शशी शर्मा, शीतल वर्मा, अनिरुद्धसाही, कैप्टन जनक राज, सुमित मरवाहा, साहिल खुराना, वरिन्द्र चोपड़ा, नीरज मूंग, जसपाल, विजय बहादर, गुशन बावा, बब्ला पासी, राकेश वैद्ध सहित अन्य भी उपस्थित रहे।

सनमती विमल जैन स्कूल का पांचवीं का परिणाम रहा शत-प्रतिशत

-चरणजीत सिंह चन्न-

जगरांव/यूटर्न/1/अप्रैल। सनमती विमल जैन स्कूल के विद्यार्थियों ने गाड़े सफलता के झंडे, 34 छात्रों ने 90% से अधिक अंक पाए।

शिक्षा के क्षेत्र में सनमती विमल जैन स्कूल का दबदबा: पांचवीं की बोर्ड परीक्षा में शिवम, तमन्ना, कीर्ति, वृष्टि और प्रभदीप रहे अव्वल। 127 में से 34 छात्र 90% के पार: सनमती विमल जैन स्कूल के शानदार परीक्षा परिणाम से खुशी की लहर।

राजय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (SCERT) द्वारा घोषित पांचवीं कक्षा के परिणामों में सनमती विमल जैन सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल, जगरांव का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा। हर साल की तरह इस बार भी स्कूल का परिणाम 100 प्रतिशत रहा।

मुख्य आकर्षण: प्रथम स्थान: शिवम कुमार, तमन्ना, कीर्ति, वृष्टि और प्रभदीप सिंह ने 500 में से 500 अंक प्राप्त कर स्कूल का नाम रोशन किया।

द्वितीय स्थान: जसमीत कौर और अमोली कुमारी ने 492 अंक (98.40%) हासिल किए।

तृतीय स्थान: हरमीत कौर ने 491 अंक (98.20%) प्राप्त कर तीसरा स्थान पाया।

कुल 127 विद्यार्थियों में से 34 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए। स्कूल की प्रिंसिपल मैडम सुप्रिया खुराना, प्रबंध समिति के अध्यक्ष रमेश जैन और सचिव महावीर जैन ने बच्चों का मुंह मीठा करवाकर उन्हें बधाई दी और भविष्य में और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर स्कूल का स्टाफ भी मौजूद रहा।

जगराओं में कूड़े के ढेरों ने भड़काई सियासत

पार्षद का कार्यकारी प्रधान पर 5 लाख की रिश्वत ऑफर करने का सनसनीखेज आरोप

-चरणजीत सिंह चन्न-

जगरांव/यूटर्न/1/अप्रैल। जगरांव शहर में नगर परिषद की कथित लापरवाही और बदइंतजामी के खिलाफ लोगों का गुस्सा अब सड़कों पर फट पड़ा है। वार्ड नंबर 6 के हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि लोगों का जीना दूभर हो गया है। कूड़े के पहाड़, बदबू, धुएं और ओवरफ्लो सीवरेज ने पूरे इलाके को मानो नरक बना दिया है। इसी के विरोध में वार्ड पार्षद जरनैल सिंह लोहट की अगुवाई में सैकड़ों लोगों ने जगरांव-बरनाला मुख्य मार्ग को जाम कर दिया, जिससे शहर की ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई।

गुस्साए लोग पहले नगर परिषद दफ्तर पहुंचे, लेकिन वहां कार्यकारी अधिकारी मोहित शर्मा और कार्यकारी प्रधान कंवरपाल सिंह की गैरमौजूदगी ने आग में घी डालने का काम किया। प्रशासन की इस बेरुखी से भड़के लोगों ने झांसी रानी चौक में धरना देकर सड़क जाम कर दी। हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि राहगीरों और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। धरने पर बैठे लोगों ने साफ कहा कि कूड़े के ढेरों से उठती जहरीली बदबू, उनमें लगाई जा रही आग का धुआं और सड़कों पर बहता सीवरेज का गंदा पानी उनके बच्चों की सेहत के लिए

खतरा बन चुका है। बच्चे रोज गंदे पानी से होकर स्कूल जाने को मजबूर हैं, लेकिन नगर परिषद आंखें मूंदे बैठी है।

पार्षद जरनैल सिंह लोहट ने नगर प्रशासन पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने कई बार अधिकारियों से गुहार लगाई, लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं की। मजबूर होकर जनता को सड़क पर उतरना पड़ा। मौके पर पहुंचे डीएसपी जसविंदर सिंह ढींढसा और थाना प्रभारी परमिंदर सिंह ने हालात संभालने की कोशिश की, लेकिन लोग लिखित आश्वासन पर अड़े रहे। आखिरकार प्रशासन को झुकना पड़ा और कार्यकारी प्रधान कंवरपाल सिंह, उपप्रधान जगजीत सिंह जग्गी समेत एम.ई अशोक कुमार मौके पर पहुंचे। लंबी बातचीत के बाद लिखित भरोसा दिया गया कि कूड़ा उठाने के लिए 58 लाख रुपए का प्रस्ताव तैयार है और 10 दिनों के भीतर काम शुरू कर दिया जाएगा। इसके बाद धरना समाप्त हुआ।

धरने में बड़ा धमाका: 10 लाख की रिश्वत ऑफर का आरोप

यह पूरा मामला उस समय और ज्यादा गरमा गया जब पार्षद जरनैल सिंह लोहट ने सबके सामने कार्यकारी प्रधान कंवरपाल सिंह पर गंभीर और सनसनीखेज आरोप जड़ दिए। लोहट ने दावा किया कि उन्हें पहले 5 लाख रुपए देने की पेशकश की गई थी। यह रिश्वत कथित तौर पर पूर्व प्रधान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में समर्थन हासिल करने के लिए दी जा रही थी। उन्होंने दो टूक कहा, 'मैं बिकाऊ नहीं हूं। मैंने अपने ईमान के साथ समझौता नहीं किया और उसी की सजा आज मेरा वार्ड भुगत रहा है। हमारे इलाके के विकास कार्य जानबूझकर रोके जा रहे हैं।'

कार्यकारी प्रधान का जवाब: आरोपों से पल्ला झाड़ा

जब इन गंभीर आरोपों पर कार्यकारी प्रधान कंवरपाल सिंह से जवाब मांगा गया, तो उन्होंने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि यह सब झूठ है और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि, वह इस मुद्दे पर ज्यादा बोलने से बचते नजर आए और सवालों से कन्नी काट गए।

नगर परिषद की कार्यप्रणाली पर उठे बड़े सवाल

इस पूरे घटनाक्रम ने जगरांव नगर परिषद की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ शहर के लोग कूड़े और गंदगी में जीने को मजबूर हैं, वहीं दूसरी तरफ सियासी आरोप-प्रत्यारोप और रिश्वत के गंभीर आरोप व्यवस्था की पोल खोल रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या 10 दिनों में सचमुच सफाई अभियान शुरू होगा? क्या रिश्वत के आरोपों की निष्पक्ष जांच होगी? या फिर यह मामला भी बाकी मुद्दों की तरह ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? फिलहाल, जगरांव की जनता जवाब मांग रही है और इस बार सवाल सीधे सिस्टम से हैं।

मजदूर-कर्मचारी विरोधी 'चार लेबर कोड' के खिलाफ फूटा गुस्सा

जगराओं डिपो पर मनाया गया 'काला दिवस'

-चरणजीत सिंह चन्न-

जगरांव/यूटर्न/1/अप्रैल। आज ट्रेड यूनियनों के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर केंद्र और राज्य सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ 'काला दिवस' मनाया गया। इसी कड़ी में पंजाब रोडवेज, पनबस और पीआरटीसी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर यूनियन के सदस्यों ने जगरांव डिपो के गेट पर इकट्ठा होकर भारी रोष प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने हाथों में काले झंडे लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और लेबर कोड को लागू करने के फैसले को तानाशाही करार दिया।

मजदूरों का मानसिक और शारीरिक शोषण है लेबर कोड: जलौर सिंह... यूनियन के पंजाब ज्वाइंट सेक्रेटरी जलौर सिंह ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यदि सरकार इन चार लेबर कोड को लागू करती है, तो यह सीधे तौर पर श्रमिकों का मानसिक और शारीरिक शोषण होगा। उन्होंने कहा कि सरकार पूंजीपतियों के साथ मिलकर सरकारी संस्थानों

को खत्म करने की साजिश रच रही है।

प्रदर्शन के मुख्य बिंदु: ठेका प्रथा का विरोध: वक्ताओं ने कहा कि सरकारी विभागों में ठेकेदारी प्रथा के जरिए कम वेतन देकर वर्करों का शोषण किया जा रहा है।

निजीकरण पर हमला: ट्रांसपोर्ट विभाग में 'किलोमीटर स्कीम' के तहत प्राइवेट बसों को शामिल करना विभाग के निजीकरण की ओर एक कदम है, जिससे रोजगार खत्म हो रहे हैं और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है।

पुरानी यादें और चेतावनी: नेताओं ने याद दिलाया कि बीती 12 फरवरी को भी देशव्यापी हड़ताल कर इन कोडों का विरोध किया गया था, लेकिन सरकार लगातार कर्मचारी विरोधी फरमान जारी कर रही है।

पक्की भर्ती पर रोक: सरकार भविष्य में नियमित भर्तियों पर रोक लगाकर सरकारी ढांचे को कमजोर कर रही है। अगर सरकार ने इन कर्मचारी विरोधी फरमानों को वापस नहीं लिया या इन्हें जबरन लागू करने की कोशिश की, तो आने वाले समय में ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर और भी तीखा संघर्ष किया जाएगा।

जिला होशियारपुर में शाम 7 बजे से सुबह 10 बजे तक कम्बाइनों से गेहूं काटने पर पाबंदी

गेहूं की पराली या फसल के अवशेष को आग न लगाने की अपील

दलजीत अज्नोहा

होशियारपुर//यूटर्न/01 अप्रैल। जिला मजिस्ट्रेट आशिका जैन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जिला होशियारपुर में शाम 7 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक कम्बाइनों से गेहूं काटने पर पाबंदी लगाने के आदेश जारी किए हैं।

इसके साथ ही उन्होंने गेहूं की कटाई करने वाली कम्बाइनों के मालिकों को निर्देश दिए कि वे हार्वेस्टर कम्बाइन का उपयोग करने से पहले कृषि विभाग के माध्यम से मशीन की अनिवार्य जांच (इंस्पेक्शन) करवाएं और कोई भी कम्बाइन हार्वेस्टर सुपर एस.एम.एस. लगाए बिना न चलाया जाए।

ये आदेश 31 मई 2026 तक लागू रहेंगे।

जारी आदेशों के अनुसार, गेहूं काटने वाली कम्बाइनें 24 घंटे काम करती हैं और रात के समय ओस पड़ने के कारण गीली गेहूं को काट लेती हैं। इससे गेहूं में नमी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से यह सरकारी निर्धारित मानकों से अधिक नमी वाली हो सकती है। ऐसी गेहूं को खरीद एजेंसियां खरीदने में असमर्थ रहती हैं, जिससे किसानों को गेहूं बेचने में बिना वजह मंडियों में परेशान होना पड़ता है। इसलिए इन आदेशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जाए। जिला मजिस्ट्रेट ने यह भी अपील की है कि गेहूं की पराली या फसल के अवशेष को आग न लगाई जाए, क्योंकि इससे स्वच्छ वातावरण प्रदूषित होता है।

गांव नूरपुर जट्टां में डॉ. अंबेडकर के बुत की बेअदबी के दोषियों को सरकार तुरंत गिरफ्तार करे - ठेकेदार भगवान, एडवोकेट मान, दलजीत राय

दलजीत अजनोहा

हुशियारपुर/यूटर्न/01 अप्रैल। बहुजन समाज पार्टी पंजाब के जनरल सचिव ठेकेदार भगवान दास सिद्धू, हलका चबेवाळ के इंचार्ज एडवोकेट पलविंदर माना, जिला अध्यक्ष दलजीत राय ने विधानसभा हलका गढ़शंकर के गांव नूरपुर जट्टां में संविधान निमार्ता बाबा साहिब डॉ. बी.आर. अंबेडकर जी के बुत की हुई बेअदबी की सख्त शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि सरकार बेअदबी करने वाले दोषियों को तुरंत गिरफ्तार करे और सख्त सजा का प्रावधान करे। उन्होंने कहा कि बार-बार डॉ. अंबेडकर के बुतों को नुकसान पहुंचाना किसी गहरी साजिश का हिस्सा हो सकता है और पंजाब के माहौल को और खराब करने की साजिश घड़ी जा रही है जो बहुत चिंताजनक है। बसपा नेताओं ने कहा कि पंजाब में आप सरकार के चलते अब तक 9 बार बाबा साहिब के बुतों की बेअदबी हो चुकी है, पर बसपा द्वारा वार-वार मांग करने के बावजूद न तो पंजाब की 'आप' सरकार ने और न ही केंद्र की भाजपा सरकार ने सुरक्षा के कोई पुख्ता इंतजाम किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकारों की यह चुप्पी साबित करती है कि केंद्र और पंजाब की दोनों सरकारों की मानसिकता अंबेडकर विरोधी है और ये पार्टियां डॉ. अंबेडकर की विचारधारा को खत्म करने की कोशिश कर रही हैं। इन अंबेडकर विरोधी मानसिकता वाली सरकारों को लोग जल्द ही चलता कर देंगे। बसपा नेताओं ने कहा कि बसपा पंजाब के अध्यक्ष डॉ. अवतार सिंह करीमपुरी की अगुवाई हेठ पंजाब संभालो मुहिम सफलता पूर्वक आगे बढ़ रही है, जिससे पंजाब वासियों का ध्यान भटकाने के लिए ऐसी गैरकानूनी, गैरसामाजिक कार्यवाहियों अंजाम दी जा रही हैं।

फर्जी मेडिकल टेस्ट करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, BBA ड्रॉपआउट मास्टरमाइंड अरेस्ट, लग्जरी लाइफ जीने के लिए बनाया रैकेट

सिविल अस्पताल स्टैंड के ठेके की आड में चला रहे थे रैकेट, टोनी था सहयोगी

लुधियाना/यूटर्न/1 अप्रैल। खन्ना में पुलिस ने एक फर्जी मेडिकल और डोप टेस्ट रैकेट का भंडाफोड़ किया है। इस रैकेट ने सरकारी व्यवस्था में सेंध लगाकर लंबे समय से अवैध कमाई की। इस गिरोह का मास्टरमाइंड 23 वर्षीय बीबीए ड्रॉपआउट मंचित कुमार है, जो कम समय में अमीर बनने की चाहत रखता था। जांच में सामने आया कि मंचित कुमार ने पहले क्रिप्टोकरेंसी में निवेश किया, लेकिन लाभ नहीं मिला। इसके बाद उसने अपराध की दुनिया में कदम रखा और एक ऐसा नेटवर्क बनाया जो पूरी तरह असली प्रतीत होता था। इस काम में लुधियाना के फील्डगंज निवासी रमेश कुमार उर्फ टोनी उसका सहयोगी था। छापेमारी के दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से कई चौंकाने वाले सामान बरामद किए। इनमें रिटायर्ड और मौजूदा एसएमओ (सीनियर मेडिकल ऑफिसर) समेत कई डॉक्टरों की फर्जी मोहरें, डोप टेस्ट की सील,

ओपीडी स्लिप, आधार कार्ड, पैन कार्ड और अन्य जरूरी दस्तावेज शामिल हैं। इनकी मदद से आरोपी असली जैसे दिखने वाले कागज तैयार कर लोगों को धोखा देते थे।

दिखाने के लिए शुरू किया साइकिल स्टैंड और पार्किंग का काम

गिरोह ने अपने अवैध धंधे को छिपाने के लिए सिविल अस्पताल में साइकिल स्टैंड और पार्किंग का काम भी शुरू कर रखा था। इसकी आड़ में वे लोगों से संपर्क करते और मोटी रकम लेकर फर्जी दस्तावेज तैयार करते थे। इस रैकेट का पदार्फाश तब हुआ जब लुधियाना के हिमांशु अरोड़ा का फर्जी डोप टेस्ट किया गया और उसे जाली सर्टिफिकेट दिया गया। इस सर्टिफिकेट की एक प्रति खन्ना के एसएमओ डॉ. मनिंदर सिंह भसीन को मिली, जिसके बाद उन्होंने तुरंत एसएसपी को शिकायत दर्ज कराई।

कोविड काल में रखी रैकेट की नींव

इस रैकेट की नींव कोविड-19 महामारी के दौरान रखी गई थी। उस समय मंचित ने खन्ना के सिविल अस्पताल में निजी तौर पर काम किया था। इस दौरान उसने अस्पताल के कामकाज, दस्तावेज तैयार करने की प्रक्रिया और अधिकारियों के हस्ताक्षर व मोहरों की बारीकियों को समझा। धीरे-धीरे मंचित और उसके साथी ने फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट, नकली डोप टेस्ट रिपोर्ट और अन्य जाली दस्तावेज बनाने शुरू कर दिए। ये दस्तावेज मुख्य रूप से शस्त्र लाइसेंस बनवाने वालों, सरकारी नौकरी के उम्मीदवारों और अदालती मामलों में पेश होने वाले लोगों के लिए तैयार किए जाते थे।

गांव जोधां में अवैध पटाखा फैक्ट्री में भयानक धमाका

19 वर्षीय युवक की मौत, 3 घायल, पुलिस ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार

-चरणजीत सिंह चन्न-

जगरांव/यूटर्न/1/अप्रैल। लुधियाना देहाती के थाना जोधां के अंतर्गत आते गांव जोधां में बीती देर शाम एक अवैध पटाखा फैक्ट्री (मकान) में भयानक धमाका होने का मामला सामने आया है। इस दर्दनाक हादसे में एक 19 वर्षीय युवक की मौत हो गई, जबकि एक नाबालिग लड़की सहित तीन अन्य व्यक्ति बुरी तरह झुलस गए। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए इस अवैध कारोबार को चलाने वाले दो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घर के अंदर पटाखा बनाने की फैक्ट्री चलने के खुलासे के बाद इलाके के लोगों में भारी दहशत और हैरानी पाई जा रही है।

कैसे हुआ हादसा

मुल्लांपुर दाखा के डीएसपी वरिंदर सिंह खोसा द्वारा दी गई जानकारी और प्रारंभिक जांच के अनुसार, 31 मार्च की देर शाम करीब 7 से 9 बजे के बीच गांव जोधां के खेतों में बने एक मकान से जोरदार धमाके की आवाज आई। पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर की गई जांच में सामने आया कि उत्तर प्रदेश (यू.पी.) से आए करीब 14-15 सदस्यों का एक परिवार पिछले 3-4 दिनों से यहां रह रहा था और गैर-कानूनी ढंग से पटाखे बनाने का काम कर रहा था। पटाखे बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली 'पोटाश' में अचानक आग लगने के कारण ब्लास्ट हुआ, जिसकी चपेट में आने से साथ लगती रसोई में रखा गैस सिलेंडर भी फट गया। इस दोहरे धमाके के कारण मकान का लेंटर (छत) नीचे गिर गया।

बचाव कार्य और जानी नुकसान

- धमाके की सूचना मिलते ही डीएसपी वरिंदर सिंह खोसा और थाना जोधां की पुलिस पार्टी सहित फायर ब्रिगेड और स्वास्थ्य विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं। धमाके के कारण मलबे के नीचे दबे और झुलसे लोगों को बाहर निकालने के लिए सिविल प्रशासन, एन.डी.आर.एफ. (NDRF) और सेना को सूचित किया गया। ग्रामीणों के सहयोग और संयुक्त बचाव अभियान के जरिए पीड़ितों को बाहर निकाला गया। इस हादसे में लेंटर के नीचे दबे 19 वर्षीय युवक कैफ मोहम्मद को निकालकर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। घायलों में 16 वर्षीय अलीशा की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है, जबकि आर्यन, जमील और एक 50 वर्षीय व्यक्ति भी झुलसने के कारण घायल हुए हैं, जिनका सिविल अस्पताल लुधियाना में इलाज चल रहा है।

पुलिस कार्रवाई और आरोपी गिरफ्तार

- डीएसपी खोसा ने बताया कि इस मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दो सगे भाइयों- वाजिद और साजिद पुत्र उलाहुद्दीन, निवासी मुजफ्फरनगर, यू.पी. को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में यह तथ्य सामने आए हैं कि ये दोनों आरोपी उक्त गरीब परिवार को मजदूरी का बहाना बनाकर यहां लाए थे और उनसे पटाखे बनाने का अवैध धंधा करवा रहे थे। दर्ज हुई एफ.आई.आर : आरोपियों के खिलाफ थाना जोधां में संबंधित कानूनों के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मकान मालिक की भूमिका की जांच : पुलिस इस बात की भी गहराई से जांच कर रही है कि जिस मकान में यह गैर-कानूनी काम चल रहा था, उसमें मालिक की क्या मिलीभगत है। दोषी पाए जाने पर मकान मालिक को भी मुकदमे में नामजद किया जाएगा। मौके पर मौजूद बाकी विस्फोटक सामग्री (पोटाश) को सुरक्षित ढंग से नष्ट (Defuse) करने के लिए सेना और प्रशासनिक टीमों के साथ मिलकर काम किया जा रहा है ताकि इलाके में किसी भी अन्य संभावित नुकसान को रोका जा सके। पुलिस द्वारा मामले की आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।

अमलाला घग्गर पुल की मरम्मत का कार्य जल्द होगा शुरू

डेराबस्सी/यूटर्न/01 अप्रैल। अमलाला घग्गर नदी पर स्थित पुल, जो ओवरलोड टिप्परों के कारण क्षतिग्रस्त हो गया है, उसकी मरम्मत का कार्य जल्द ही शुरू किया जाएगा। इस कार्य के लिए क्षेत्र के लोगों द्वारा बड़े स्तर पर आर्थिक सहयोग दिया जा रहा है। ग्रामीणों ने सहयोग देने वाले सभी दानदाताओं का आभार व्यक्त करते हुए बताया कि यह मरम्मत कार्य घड़मवाले बाबा की कारसेवा के सहयोग से शुरू किया जाएगा, क्योंकि उक्त पुल का निर्माण भी उनके माध्यम से ही कराया गया था।

इसके साथ ही गांव में पंजाब सरकार के खिलाफ पिछले नौ दिनों से धरना जारी है। धरनाकारियों का आरोप है कि डी-सीलिंग के नाम पर घग्गर नदी में अवैध खनन किया जा रहा था, जो धरना शुरू होने के बाद बंद हो गया है। हालांकि, खनन में लगे ओवरलोड टिप्परों के कारण पुल और सड़क को भारी नुकसान पहुंचा है। ग्रामीणों का कहना है कि यह पुल सरकारी नहीं, बल्कि लोगों के सहयोग और कारसेवा से बनाया गया था, इसलिए अब इसकी मरम्मत के लिए भी लोग स्वयं आगे आ रहे हैं। पूर्व सरपंच बलिहार सिंह बली ने बताया कि मरम्मत कार्य के लिए उपयोग में आने वाली तार की व्यवस्था एन.के. शर्मा द्वारा की जा रही है, जबकि भाजपा नेता गुरदर्शन सिंह सैनी द्वारा भी सहयोग राशि प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि गांव और आसपास के लोग खुले दिल से सहयोग कर रहे हैं, जिससे यह सामूहिक प्रयास शीघ्र ही सफल होगा। साथ ही उन्होंने सभी से अपील की कि इस नेक कार्य में योगदान देकर क्षेत्र की सामूहिक संपत्ति को बचाने में अपना सहयोग दें।

प्रगतिशील किसान फतेह सिंह सैनी को मुख्यमंत्री पुरस्कार

जीरकपुर/यूटर्न/01 अप्रैल। डेराबस्सी हलके के विधायक स. कुलजीत सिंह रंधावा ने प्रगतिशील किसान फतेह सिंह सैनी को मुख्यमंत्री पुरस्कार से सम्मानित होने पर हार्दिक बधाई दी है। गुरु अंगद देव वेटरिनरी एवं एनिमल साइंसेज यूनिवर्सिटी में आयोजित पशुपालन विभाग मेले 2026 के दौरान डेराबस्सी हलके के गांव छत निवासी प्रगतिशील किसान फतेह सिंह सैनी को पशुपालन के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए मुख्यमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विधायक रंधावा स्वयं उनके फार्म पर पहुंचे और उन्हें शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि फतेह सिंह सैनी ने पशुपालन के क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों को अपनाकर अपने फार्म को एक मॉडल फार्म के रूप में विकसित किया है। विधायक ने कहा कि फतेह सिंह की मेहनत और नवाचार ने न केवल उनकी आय में वृद्धि की है, बल्कि वे अन्य किसानों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बने हैं। ऐसे प्रगतिशील किसान समाज के लिए मिसाल हैं, जो खेती और पशुपालन को नई ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा पशुपालन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं और इस तरह के किसानों को सम्मानित करने से अन्य किसान भी प्रेरित होते हैं।

पंजाब को 'कैंसर की राजधानी' बनने से बचाने की मुहिम

ग्रीन पंजाब मिशन टीम ने विधायक लाडी ढोस को सौंपा मांग पत्र

-चरणजीत सिंह चन्न-

जगरांव/यूटर्न/1/अप्रैल। धरती के 33% हिस्से को वृक्षों से सजाने और पर्यावरण को बचाने के लक्ष्य के साथ 'ग्रीन पंजाब मिशन टीम' ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। इसी कड़ी में आज टीम की ओर से आम आदमी पार्टी के विधायक दविंदरजीत सिंह लाडी ढोस को एक मांग पत्र सौंपा गया।

प्रमुख मुद्दे: क्यों जरूरी है 33% वन क्षेत्र ?

टीम के मुख्य सेवादार सतपाल सिंह देहड़का ने वन सुरक्षा अधिनियम का हवाला देते हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य रखे:

नियम बनाम वास्तविकता: भारत सरकार के नियमों के अनुसार मैदानी क्षेत्रों का 33% हिस्सा जंगलों के अधीन होना अनिवार्य है, लेकिन पंजाब में यह मात्र 3 से 4 प्रतिशत ही रह गया है।

कैंसर का खतरा: देहड़का ने चेतावनी दी कि जंगलों की भारी कमी के कारण पंजाब 'कैंसर की राजधानी' बन चुका है। यदि इस 'कैंसर ट्रेन' को रोकना है, तो वृक्षारोपण ही एकमात्र समाधान है।

जल स्तर में सुधार: अधिक वृक्ष लगाने से न केवल बीमारियाँ कम होंगी, बल्कि गिरते भू-जल स्तर को सुधारने में भी मदद मिलेगी।

विधायक लाडी ढोस का बड़ा बयान

मांग पत्र स्वीकार करते हुए विधायक लाडी ढोस ने टीम के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा: मैंने विधानसभा में अपने दूसरे भाषण के दौरान भी यह मुद्दा उठाया था कि मोटरों की हॉर्स पावर (HP) के आधार पर वृक्ष लगाना अनिवार्य किया जाना चाहिए। जो किसान वृक्ष नहीं लगाएंगे, उन्हें मुफ्त बिजली का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए।

विपक्ष का भी मिला समर्थन

गौरतलब है कि टीम ने पिछले दिनों कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा को भी मांग पत्र सौंपा था।

बाजवा ने इस प्रस्ताव की सराहना करते हुए कहा था कि यदि उनकी सरकार आती है, तो वे 50% पंचायती जमीन को बागवानी (Forestry) के अधीन लाने का प्रयास करेंगे।

टीम की मुख्य मांगें: विधायक इस मुद्दे को विधानसभा में पुरजोर तरीके से उठाएं।

कम से कम 33% पंचायती जमीनों पर बागवानी/वनीकरण करने का प्रस्ताव पारित कर उसे तत्काल लागू किया जाए।

इस अवसर पर सतपाल सिंह देहड़का के साथ प्रोफेसर करम सिंह संधू, हरनारायण सिंह मल्लेआना, मेजर सिंह छीना, मैडम कंचन गुप्ता और इंस्पेक्टर जगराज सिंह सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे।

बठिंडा में पेट्रोल और डीजल की सप्लाई सुचारू, कोई कमी नहीं: डिप्टी कमिश्नर

सोनू टुटेजा

बठिंडा, यूटर्न, 01 अप्रैल। डिप्टी कमिश्नर श्री राजेश धीमान ने कहा कि जिले में पेट्रोल और डीजल की सप्लाई सुचारू रूप से जारी है और किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों में जिले की कुल 39 गैस एजेंसियों से लगभग 5 लाख उपभोक्ताओं ने गैस भरवाई है और पूरे जिले में पूरी मात्रा में गैस की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल की सप्लाई पर लगातार नजर रखी जा रही है और अब तक पेट्रोल पंपों की सप्लाई लगभग 80 प्रतिशत हो गई है। अगले कुछ दिनों में सप्लाई पूरी तरह से सामान्य होने की संभावना है और इसके लिए जिला प्रशासन जरूरी कदम उठा रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जिले भर में लगभग 60 प्रतिशत ढठऋृपाइपलाइन बिछाई जा चुकी है। संबंधित एजेंसियों के साथ लगातार सहयोग किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर श्री राजेश धीमान ने सभी ज़िला निवासियों से अपील की है कि वे पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस को बिना वजह जमा न करें। ज़िला प्रशासन हालात पर कड़ी नजर रखे हुए है और लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है।

पुलिस हिरासत में प्रताड़ना का मामला

जगरांव थाने के बाहर किसानों और मजदूरों का जोरदार प्रदर्शन

-चरणजीत सिंह चन्ना-

जगरांव/यूटर्न/1/अप्रैल। जगरांव में पुलिसिया दमन और महिलाओं पर हुए अमानवीय अत्याचारों के खिलाफ इंसाफ की आवाज एक बार फिर बुलंद हुई है। कीर्ति किसान यूनियन के दिवंगत जिला अध्यक्ष तरलोचन सिंह झोरड़ां द्वारा शुरू किए गए पक्के मोर्चे ने आज अपने पांचवें वर्ष में प्रवेश कर लिया है। इस अवसर पर विभिन्न किसान-मजदूर संगठनों ने थाने के समक्ष इकट्ठा होकर पंजाब सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।

क्या है पूरा मामला ?

यह विरोध प्रदर्शन तत्कालीन थाना प्रभारी (SHO) और चौकी इंचार्ज द्वारा महिलाओं को अवैध हिरासत में रखने और उन्हें शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के विरोध में किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि तत्कालीन एसएचओ गुरिंदर सिंह बल और एएसआई राजवीर सिंह ने जातिगत दुर्भावना के चलते दो परिवारों को जबरन उनके घरों से अगवा किया। बुजुर्ग माता सुरिंदर कौर और युवती कुलवंत कौर को अवैध हिरासत में रखकर अमानवीय यातनाएं दी गईं।

पीड़िता मनप्रीत कौर के साथ हिरासत के दौरान यौन उत्पीड़न जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया।

नेताओं ने सरकार को घेरा

धरने को संबोधित करते हुए कीर्ति किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष साधू सिंह अच्चरवाल, सचिव बलविंदर सिंह कोठे पोना और अन्य नेताओं ने पंजाब सरकार की कार्यप्रणाली पर कड़े सवाल उठाए।

'पंजाब की नकारा सरकार को सालों से धरने पर बैठे ये गरीब लोग दिखाई नहीं दे रहे। सरकार पीड़ितों को न्याय देने के बजाय दोषियों को संरक्षण दे रही है।' - किसान नेता

अधिकारियों पर दोषियों को बचाने का आरोप

मामले के मुख्य शिकायतकर्ता इकबाल सिंह रसूलपुर ने कहा कि कई जांच रिपोर्ट सामने आने के बावजूद पुलिस और नागरिक प्रशासन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने से कतरा रहा है। सबूतों को जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है, जिसके कारण अब पीड़ितों को मजबूरन अदालतों का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि अंततः सत्य की जीत होगी और दोषियों को कानून के सामने झुकना पड़ेगा। इस विरोध प्रदर्शन में कीर्ति किसान यूनियन, देहाती मजदूर सभा, मजदूर संघर्ष कमेटी, सत्कार कमेटी, जबर विरोधी फ्रंट पंजाब और पेंडू मजदूर यूनियन सहित कई जत्थेबंदियों ने शिरकत की। मौके पर भारी संख्या में किसान और मजदूर नेता मौजूद रहे, जिन्होंने संकल्प लिया कि जब तक दोषियों को सजा नहीं मिलती, यह संघर्ष जारी रहेगा।

बाइक सवार ने गले से सोने की चेन झपटी, फरार

जीरकपुर/यूटर्न/01 अप्रैल। साउथ सिटी सोसाइटी के पास देर रात एक बाइक सवार झपटमार ने व्यक्ति के गले से सोने की चेन छीनकर फरार हो गया। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, पीड़ित आशीष शर्मा (39) ने बताया कि रात करीब 12:30 बजे वह अपनी सोसाइटी के पास एक परिचित को एक्टिवा चलाना सिखा रहा था। वह खुद स्कूटी के पीछे बैठा हुआ था। इसी दौरान पीछे से आए एक अज्ञात बाइक सवार ने झपट्टा मारकर उसके गले से सोने की चेन तोड़ ली और मौके से फरार हो गया। पीड़ित ने आरोपी का पीछा करने की कोशिश भी की, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर वह भागने में सफल रहा।

Sharadha Kapoor

एसएसजीआई में 'वेक्टर ट्रैजेक्टरी' छात्र क्लब का शुभारंभ

एसएसजीआई में 'वेक्टर ट्रैजेक्टरी' छात्र क्लब का शुभारंभ

डेराबस्सी/यूटर्न/01 अप्रैल। श्री सुखमनी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस (एसएसजीआई), डेराबस्सी ने छात्रों की रोजगार क्षमता बढ़ाने और शैक्षणिक शिक्षा को उद्योग की मांगों के अनुरूप ढालने के उद्देश्य से ह्यवेक्टर ट्रैजेक्टरीह्व छात्र क्लब का शुभारंभ किया है। यह पहल संस्थान द्वारा शुरू किए गए नवोन्मेषी कार्यक्रमों की श्रृंखला का हिस्सा है, जिसे उद्योग विशेषज्ञों के सहयोग से एक पेशेवर एड-टेक पहल के तहत शुरू किया गया है।

क्लब का आधिकारिक शुभारंभ संस्थान परिसर में अध्यक्ष कंवलजीत सिंह एवं निदेशक दमनजीत सिंह के संरक्षण में किया गया। शून्य बजट पर आधारित यह छात्र-संचालित तकनीकी समुदाय कक्षा शिक्षा और उद्योग की वास्तविक आवश्यकताओं के बीच की खाई को पाटने का प्रयास करेगा। इस पहल के तहत छात्र उद्योग विशेषज्ञों और संकाय सदस्यों के मार्गदर्शन में लाइव परियोजनाओं पर कार्य कर व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करेंगे। साथ ही, यह कार्यक्रम प्रतिस्पर्धी एवं सहयोगात्मक वातावरण को बढ़ावा देगा, जिससे छात्र टीम के रूप में कार्य करते हुए अन्य संस्थानों के विद्यार्थियों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे। कठोर मूल्यांकन एवं व्यक्तिगत साक्षात्कार के बाद क्लब के लिए विभिन्न नेतृत्व भूमिकाओं में छात्रों का चयन किया गया है। इनमें भूमिका सैनी को कैंपस लीड, अविनाश कुमार को वेब डेवलपमेंट लीड, मोहम्मद खुशाल को साइबर सिक्योरिटी लीड, द्विंकल सैनी को एआई/एमएल लीड तथा मानसी को मार्केटिंग लीड नियुक्त किया गया है। इस अवसर पर निदेशक दमनजीत सिंह ने कहा कि 'वेक्टर ट्रैजेक्टरी' का शुभारंभ कौशल विकास, व्यावहारिक अनुभव और बेहतर प्लेसमेंट परिणामों पर केंद्रित एक सशक्त शिक्षण वातावरण तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। कार्यक्रम में मुख्य प्रशासक प्रो. रशपाल सिंह, टीपीओ डॉ. रविंदर तथा एसएसजीआई के अंतर्गत विभिन्न संस्थानों के प्रधानाचार्य भी उपस्थित रहे।

न्यू यंग फाइव स्टार क्लब का महावीर जयंती पर 49वे रक्तदान कैंप, लुधियानवियों ने उत्साह से किया 922 यूनिट रक्तदान

सेवा कार्यों के लिए सभी लुधियानवियों का धन्यवाद,:- राजेश जैन बॉबी

लुधियाना/यूटर्न/01 अप्रैल। अहिंसा के पुजारी श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के जन्म कल्याणक के मौके पर न्यू यंग फाइव स्टार क्लब, भोले बाबा रत्न मुनि जैन युवा सोसायटी एवं मां वैष्णो देवी चैरीटेबल अस्पताल लुधियाना की ओर से किंग पैलेस, सुन्दर नगर लुधियाना में 49वा रक्तदान कैंप का भव्य आयोजन किया गया जिसमें युवक-युवतियों ने 922 रक्त यूनिट रक्त दिया।कैंप में मुख्य संरक्षक व मार्कीट कमेटी के पूर्व चेयरमैन दर्शन लाल बवेजा,अंसल एस्टेट के एस एस खुराना,विजय बवेजा,बिपन जैन, विधायक मदन लाल बग्गा,विधायक अशोक पराशर पप्पी,विधायक दलजीत भोला, डिप्टी मेयर राकेश पराशर,पवन दीवान,ममता आशु,पार्षद अरुण शर्मा,पार्षद नीरज आहूजा बूटा, पार्षद प्रदीप गैबी,जॉइंट कमिश्नर जसदेव सेखों,नीरज जैन,एडवोकेट गौरव बग्गा खुराना,विपन सूद काका,बिट्टू नैय्यर, एडवोकेट वरिंदर शर्मा बॉबी,मोहन लाल गुप्ता,संजीव बांका, समाज सेवक संचित मल्होत्रा,प. अजय वशिष्ठ, पार्षद पल्लवी विनायक,कुंज गर्ग, उस्मान रहमानी, विजय दानव,मुनिश शाह,इंद्रजीत इंडी,गुरदेव शर्मा देबी, संजय तलवार,सुंदर डावर, बिट्टू गुंबर,विपन अरोड़ा,शाम सुंदर मल्होत्रा,डिंपल राणा, बाबा मीना शाह, बंटी बाबा,साहिल खुराना,राशि अग्रवाल,विकास गोयल विक्की, मनु जैरथ,अशोक थापर, यशपाल चौधरी,दिनेश मरवाहा,संजय थापर, राजीव टंडन,गोरा थापर, एडवोकेट हर्ष शर्मा, टी एस थापर,संजीव गुप्ता,राकेश बजाज,हरकेश मित्तल,भानु प्रताप, गोल्डी सभरवाल आदि ने शिरकत की।इस अवसर पर संस्था के संरक्षक समाज सेवक कीमती लाल जैन, प्रधान युवा रत्न राजेश जैन बॉबी, चेयरमैन राजेश जैन मोनिका, कपिल जैन, एडवोकेट संदीप बहल,राजकुमार जैन राजू, सचिन जैन, गोयम जैन, ऋषभ जैन योनैक्स, विजय बवेजा, मोहन लाल गुप्ता, जे के जैन,जीवन गुप्ता, अशोक धवन,सुंदर दास धमीजा,तेजस शर्मा, योगेश हांडा,अमित गुप्ता, हरविन्द्र सिंह आदि गण्यमान्य मौजूद थे। राजेश जैन बॉबी ने बताया कि रक्तदान से बढ़कर कोई दान नहीं है। हर स्वस्थ व्यक्ति को रक्तदान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि युवाओं द्वारा ही समाज में फैली बुराइयों को खत्म कर समाज में जागृति लाई जा सकती है। जो दान किसी को जीवन दे, वह सबसे बड़ा महादान होता है। उन्होंने सेवा कार्यों के लिए सभी लुधियानवियों का धन्यवाद व्यक्त किया।

अमेरिका की शीर्ष कंपनियों का वैश्विक दबदबा, मिडिल ईस्ट तनाव के बीच दुबई पर खतरे की चर्चा तेज

नई दिल्ली/दुबई/यूटर्न/01 अप्रैल। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था United States की शीर्ष कंपनियां आज वैश्विक बाजार को दिशा दे रही हैं। Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet Inc. और NVIDIA जैसी कंपनियां टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल इकोनॉमी में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। वहीं Tesla, Meta Platforms, Berkshire Hathaway, JPMorgan Chase और ExxonMobil जैसे दिग्गज ऊर्जा, बैंकिंग और निवेश क्षेत्र में वैश्विक प्रभाव बनाए हुए हैं। इन कंपनियों का असर केवल अमेरिकी अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के बाजारों पर पड़ता है।

इसी बीच मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव, खासकर ईरान-इजराइल टकराव के चलते Dubai को लेकर भी सुरक्षा चिंताएं सामने आ रही हैं। दुबई वैश्विक व्यापार, पर्यटन और वित्त का प्रमुख केंद्र है, जहां से अंतरराष्ट्रीय कारोबार का बड़ा हिस्सा संचालित होता है। इसकी भौगोलिक स्थिति, विशेषकर ईरान के नजदीक होने और खाड़ी क्षेत्र में रणनीतिक महत्व के कारण इसे संभावित जोखिम वाले शहरों में गिना जा रहा है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि क्षेत्रीय संघर्ष और बढ़ता है तो दुबई जैसे प्रमुख शहरों पर अप्रत्यक्ष असर पड़ सकता है। हालांकि संयुक्त अरब अमीरात की मजबूत सुरक्षा व्यवस्था, अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के चलते फिलहाल किसी बड़े हमले की पुष्टि नहीं है। आर्थिक जानकारों के अनुसार, यदि मिडिल ईस्ट में हालात बिगड़ते हैं तो इसका असर वैश्विक तेल कीमतों, शेयर बाजार और अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर पड़ेगा। भारत सहित कई देशों के लाखों लोग दुबई में काम करते हैं, ऐसे में किसी भी अस्थिरता का सीधा प्रभाव प्रवासी समुदाय और व्यापारिक गतिविधियों पर पड़ सकता है। कुल मिलाकर, जहां एक ओर अमेरिकी कंपनियां वैश्विक अर्थव्यवस्था को दिशा दे रही हैं, वहीं दूसरी ओर मिडिल ईस्ट का बढ़ता तनाव अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई चुनौतियां खड़ी कर रहा है।

पंजाब ने स्वास्थ्य सेवा योजना तक पहुंच के लिए 19,000 आशा कार्यकर्ताओं को किया तैनात

चंडीगढ़/यूटर्न/01 अप्रैल। पंजाब सरकार ने स्वास्थ्य सेवा योजना तक पहुंच के लिए 19,000 आशा कार्यकताओं को तैनात किया है। प्रदेश सरकार ने 'मुख्यमंत्री सेहत योजना' (एमएमएसवाई) के तहत नामांकन की प्रक्रिया को तेज करने के लिए आशा (मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता) कार्यकताओं के नेटवर्क को सक्रिय कर दिया है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को अंतिम छोर तक मजबूत बनाना है। बुधवार को जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, अब 19,000 से अधिक आशा कार्यकर्ता और 900 सहायक राज्य भर के गांवों में पंजीकरण का काम संभाल रहे हैं।

Owner, Publisher, Printer: - Komal Sharma, Printed by DB Corp LTD VPO Hamira, Distt Kapurthala-144601 (PB), Published by: House No 68, New Sarabha Nagar, VPO Daad, Ludhiana (PB) - 142022, Editor: Sandeep Sharma
तमाम प्रकाशित सामग्री के चयन व संपादन हेतु आरबीएक्ट के तहत जिम्मेवार।
Contact - +91 9814295372